डाक पंजीयन क्र. L/ RNP/म.प्र./ मन्दसौर/122/ 2024- 26

ई-पेपर www.guruexpress.live

बात आपकी, शब्द हमारे

गुरु एक्सप्रेस

सुबह का अखबार

संपादक – आशुतोष नवाल

वर्ष 18 | अंक 238 | पृष्ठ 4 | मन्दसौर | बुधवार 12 जून 2024 | मूल्य 2 रुपया

चीतों के नए घर गांधी सागर अभ्यारण्य पर अब नई सरकार लेगी निर्णय

भोपाल, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। चीतों के लिए नया ठिकाना अब केंद्र की नई सरकार तय करेगी। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के चलते इस पर निर्णय नहीं हो सका था। आचार संहिता हटने के बाद दिल्ली में 10 जून को बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन मोदी कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह के चलते बैठक निरस्त कर दी गई।

श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क के अतिरिक्त चीतों को अन्य स्थान पर भी बसाने का निर्णय अगली बैठक में लिया जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश में ही गांधी सागर अभयारण्य लगभग तैयार कर लिया गया है। चीतों की खुराक लिए यहां 300 से अधिक चीतल छोड़े जा चुके हैं।

पुराना प्लान निरस्त कर नया प्लान किया स्वीकृत...

गांधी सागर में चीता पुनर्वास का पुराना प्लान निरस्त कर नया प्लान स्वीकृत कर दिया गया है। वन विभाग ने वनमंडल मंदसौर के अंतर्गत गांधी सागर अभयारण्य अंतर्गत चीता पुनर्वास के लिए वन्यप्राणी संरक्षण एवं रहवास विकास कार्यों के लिए 31 अगस्त 2022 को 84 लाख रुपये के चार वर्षीय प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया था, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को निरस्त कर दिया गया है। इसके पीछे कारण बताया गया कि यह प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्लान के अनुरुप नहीं था। इसके स्थान पर अब 10 वर्षीय प्लान स्वीकृत किया गया है, जिसमें 43 लाख 20 हजार रुपये की राशि मंजूर की गई है। यह राशि टाइगर फाउंडेशन समिति से ली जाएगी।

इन गतिविधियों पर होगा व्यय...

नए दस वर्षीय प्लान के अनुसार, गांधी सागर अभयारण्य में वन्यप्राणियों के लिए वाटर सोर्स पर दो लाख रुपये, वन्यजीवों के संरक्षण के लिए बुनियादी ढांचे, बचाव वार्ड, पशु चिकित्सा निधि, पिंजरों आदि के निर्माण के लिए चार लाख रुपये, रावलीकुडी बीट में जलाशय बनाने पर 11 लाख रुपये। बीट करनपुरा में जलाशय की मरम्मत पर छह लाख रुपये, बीट खेमला पश्चिम क्रमांक 449 में जलोद्धार के लिए तीन लाख रुपये, बीट रावलकुडी क्रमांक 944 में जलोद्धार के लिए तीन लाख रुपये, नीमचौक में चीता फेंसिंग क्षेत्र में चारागाह विकास के लिए छह लाख रुपये, गांधीसागर में कैम्पों, खेल व क्वीज कम्पीटीशन के माध्यम से जागरुकता कार्यक्रम चलाने पर 5 लाख 20 हजार रुपये और थर्ड पार्टी मानीटरिंग के लिए एक लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

भागवत चिंता पर ईमानदारी से चिंतन करे भाजपा...

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बार फिर राष्ट्र-हित के व्यापक दृष्टिकोण के मद्देनजर अपने बड़प्पन का परिचय दिया है। यह आचरण उस पिता की तरह है, जो संतान से नाराज होने के बाद भी यह सोचकर उसे सलाह देता है कि आखिरकार मामला पूरे घर की भलाई का ठहरा। इसीलिए संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने सोमवार को जो कुछ कहा, उसमें यदि उनका गुस्सा झलक रहा था तो इस बात की फिक्र भी थी कि आखिरकार मामला पूरे देश की भलाई का है। भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक संगठन के प्रमुख के रूप में भागवत ने इस दल को एक बार फिर उसकी भटकती दिशा के लिए चेताया है, ताकी भाजपा की दशा में और गिरावट को समय रहते थामा जा सके।

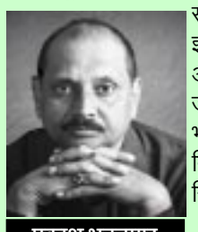

प्रकाश भटनागर

लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भागवत के जरिए संघ ने जिस तरह मुंह खोला है, उससे शायद आज की भाजपा के कर्ताधर्ता समूह का मुंह अवाक मुद्रा में खुला रह जाना स्वाभाविक है। इससे शायद उस जुबान पर लगाम भी लग सके, जिसके प्रयोग के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव के बीच दंभोक्ति की थी कि भाजपा को अब संघ की आवश्यकता नहीं है। नड्डा का यह कथन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मूक स्वीकृति का प्रतीक हो सकता है। इन दो नेताओं ने भी इसके प्रतिवाद का कोई उपक्रम नहीं किया। वह नादान होते हैं, जो ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इस काम के लिए इस्तेमाल की गई सीढ़ी को ही गिरा देते हैं।

भाजपा के सियासी उत्थान का सफर संघ के बिना संभव नहीं था, आगे भी ऐसा होना मुश्किल है। मोदी, शाह और नड्डा के समूह ने इस तथ्य से आंख मूंदकर जो दंभ दिखाया, वह संघ को पर्याप्त अवसर दे रहा था कि लोकसभा चुनाव में मोदी मय भाजपा की क्षमता (अपने दम पर बहुमत हासिल न कर पाना) को देखने के बाद इधर से मुंह फेर ले। लेकिन बात देश की है, इसलिए भागवत ने किसी अच्छे अभिभावक वाले बड़प्पन का परिचय देते हुए आज के भाजपा को उसके बीते हुए कल के मूल सिद्धांतों की तरफ लौटने की हिदायत दी है।

डॉ. भागवत का यह कथन मायनेखेज है, 'जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, गर्व करता है, किन्तु लिप्त नहीं होता, अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में स्वयंसेवक कहलाने का अधिकारी है।' उन्होंने यह भी कहा 'हमें इस मानसिकता से छुटकारा पाना होगा कि सिर्फ हमारा विचार ही सही है, दूसरे का नहीं।' जाहिर तौर पर यह सीख उस भाजपा के लिए है, जो इस आम चुनाव के काफी पहले से लगातार घमंड में चूर होकर अनेक मौकों पर अमर्यादित आचरण से भी पीछे नहीं रही। यहां बात को समझने के लिए सुभीते के तौर पर 'ये मोदी की गारंटी है' या 'मोदी है तो मुमकीन है' वाले नारों और मोदी की ब्रांडिंग से समझा जा सकता है। संघ प्रमुख का 'स्वयं को सही एवं दूसरों को गलत मानने' वाली प्रवृत्ति पर प्रहार भी भाजपा के लिए यह चेतावनी है कि वह नड्डा के उम्र उल्लेखित विचार और उसके अनुरूप हुए मोदी तथा शाह के व्यवहार से बचे। फिर डॉ. भागवत जिस समय चुनाव में 'विरोधी को पीछे धकेलने के लिए सीमा का उल्लंघन न करने' तथा 'झूठ का सहारा न लेने' की बात कहते हैं, तब यह साफ है कि संघ को चुनाव में भाजपा के प्रचार तंत्र की शैली पर भी सख्त आपत्ति है।

अब देखिए। आम चुनाव में भाजपा की कमजोरी का जहां भी निरपेक्ष तरीके से अवलोकन/विश्लेषण हो रहा है, वहां इस दल की वही गलतियां प्रमुख रूप से गिनाई जा रही हैं, जिनको लेकर भागवत ने सोमवार को अपनी बात रखी। संघ प्रमुख की चिंता के केंद्र में जो दिखा, आखिर वह सब भी तो इस बात की बहुत बड़ी वजह बना कि इस चुनाव में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कई तरह से हिंसक संघर्ष की हद तक पहुंच गई। यह बात सही है कि भाजपा और एनडीए सहित विपक्ष का भी शायद ही कोई भी दल इस सारी गंदगी से अछूता रहा हो, लेकिन अंतत: इसका सर्वाधिक श्रेय भाजपा को जाता है और इसका नुकसान भी भाजपा को ही उठाना पड़ा है। भाजपा को शक्तिशाली बनाकर राष्ट्र निर्माण के अपने यज्ञ में निरंतर परिश्रम की आहुति देते संघ को आज 'पूत कपूत तो क्या धन संचय?' वाली मुद्रा अपनानी पड़ गई है। कहा गया है, 'बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। मूल्यवती होती सोने की, भस्म यथा सोने से।' चुनावी रण के मैदान में अपने स्तर पर गिरते प्रदर्शन के बाद भी भाजपा अब तक इसे अपनी सफलता बताकर अकड़ से भरी दिख रही है। हालांकि सबसे बड़ा दल और स्थिर सरकार देने की स्थिति में वो ही है भी। और अगर भाजपा यहां से नीचे नहीं गई है तो इसका श्रेय भी मोदी के खाते में तो जाएगा ही। लेकिन, स्थिति वही है कि रस्सी जल गई, लेकिन बल नहीं गए। भाजपा के पास अब भी समय/अवसर है। वह डॉ. भागवत की बात को पूरी चिंता के साथ अपने चिंतन का विषय बनाए। मान ले कि चुनाव ने उसकी आगे की उम्मीदों को क्षीण किया है। इस विश्वास के साथ कि उसकी उम्मीदों का जो स्वर्ण अपने ही द्वारा लगाई गई आग में भस्म हो गया, भाजपा उसे स्वर्ण भस्म के रूप में और मूल्यवान स्वरूप देने की क्षमता आज भी रखती है। इस सबका रास्ता भागवत की सीख से होकर ही गुजरता है।

दिल्ली- मुंबई एक्सप्रेस वे पर भी कट..!

शार्टकट के चक्कर में हो रही दुर्घटनाए

मंदसौर, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। राजमार्ग के बाद अब हाल ही में बने दिल्ली- मुंबई एक्सप्रेस वे पर भी अवैध कट दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। दो दिन पहले जावरा क्षेत्र में अवैध कट से चढक़र डिवाइडर के बीच व किनारे बकरियां चरा रही महिला और युवती को पिकअप ने रौंद दिया। जिससे दोनों की मौत हो गई। इस तरह के हादसे और भी हुए है। बड़े कट से शार्टकट के चक्कर में ग्रामीण 8-लेन पर चढ़कर खेत जाते हैं या मवेशी-बकरियां चराते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कलवर्ट-पुलिया तक जाने की एप्रोच सही नहीं की गई, इसलिए मजबूरी में ऊपर से निकल रहे हैं।

समानांतर सड़क नहीं...

एक्सप्रेस-वे निर्माण के वक्त से ही ग्रामीण दोनों तरफ 10-15 फीट चौड़ा कच्चा समानांतर रोड बनाने की मांग करते रहे। ट्रॉयल लेने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आए थे, तब उन्होंने स्टेट से प्रस्ताव आने पर स्वीकृति की बात कही थी। लेकिन, बाद में कुछ नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि समानांतर रास्ता नहीं दिया। लेकिन, कम से कम ग्रामीण रोड से कलवर्ट-पुलिया तक आने-जाने का जो कच्चा रास्ता है, उसमें मुरमीकरण कर दें तो भी कुछ हद तक समस्या हल हो जाएगी।

कई जगहों पर कट...

गरोठ से निकल रहे एक्सप्रेस वे में कई जगहों पर बड़े अवैध कट हैं। ग्रामीण अपने खेतों पर आने-जाने के लिए तथा एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए भी इन अवैध कट से एक्सप्रेस-वे पर चढ़ते हैं। कई लोग एक्सप्रेस-वे के किनारे उगी घास तथा डिवाइडर के बीच पौधों के साथ लगी घास में मवेशी व बकरियां चराते हैं। ये इनके लिए तो घातक हैं ही बल्कि एक्सप्रेस-वे पर निकलने वालों के लिए भी बहुत खतरनाक हैं।

विरोध के बाद लौटना पड़ा...

जहां भी पहले से पक्के रोड थे, वहां छोटी पुलिया बनाई है। औसत 250 मीटर दूरी पर पानी निकासी के लिए कल्वर्ट हैं, जिनके नीचे से ग्रामीण आसानी से एक्सप्रेस-वे क्रॉस कर सकते हैं लेकिन, वे वहां से नहीं जा रहे और शॉर्ट-कट के चक्कर में अवैध कट से ऊपर चढ़रहे। हम 25 मई को पुलिस बल के साथ कट बंद करने गए थे। लेकिन, ग्रामीणों ने इतना विरोध किया कि वापस लौटना पड़ा।

संदीप पाटीदार
प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई मप्र

साढ़े पांच सौ पुलिस वालों ने खंगाले बदमाशों के ठिए

183 को पकड़ा, जिला बदर बदमाश नितेश बांछड़ा भी मिला

मंदसौर, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। जिले में करीब साढ़े पांच सौ पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों ने रातभर बदमाशो के ठिए खंगाले। दरअसल कॉम्बिंग गश्त में आरोपियों की धरपकड़ का अभियान चलाया गया। जिसमें जिले के सभी थानों का स्टॉफ लगा रहा। इस दौरान 183 लोग मिले। इनमें से किसी का वारंट तामिल कराया तो किसी का गिरफ्तारी वारंट होने से उसे पकड़ा गया। इस बीच नाहरगढ़ पुलिस ने जिला बदमाश नितेश पिता जगदीश बांछड़ा और उसके साथी अजय पिता प्रभुलाल चौहान जाति बांछड़ा दोनो निवासी निरधारी को पकड़कर एक प्रकरण और दर्ज किया।

पुलिस कप्तान श्री अनुराग सुजानिया ने बताया कि कॉम्बिंग गश्त के दौरान मल्हारगढ पुलिस द्वारा तस्करी के मामले में फरार चल रहे पांच हजार रुपए के इनामी बदमाश सुनील पिता आनंदीलाल डांगी निवासी पल्दुनी थाना अरनोद जिला प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया। इसी तरह पिपलियामंडी थाना पुलिस ने अपहरण, गैंग रेप जैसे संगीन अपराध में एक साल से फरार चल रहे पांच हजार के इनामी बदमाश विनोद पिता गणपत बावरी निवासी धामनिया (छोटी सादडी) जिला प्रतापगढ़ राजस्थान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त के दौरान जिले में 184 वारंट तामील करवाए। इसमें 93 स्थायी वारंटी व 79 गिरफ्तारी वारंट तामिल करवाए गए। वहीं जिलाबदर किए गए 3 आरोपी आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए गए। जिन्हें कॉम्बिंग गश्त के दौरान गिरफ्तार किया गया। इसकेसाथ ही पुलिस ने 183 हिस्ट्रीशीटर, गुंडे बदमाशों की चेकिंग की गई। कॉम्बिंग गश्त के दौरान आर्म्स एक्ट के 5 व मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत 1 कार्रवाई की गई।

देर रात अचानक अफजलपुर थाने पहुंचे कप्तान

सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात में पुलिस कप्तान श्री अनुराग सुजानिया अचानक अफजलपुर थाने पहुंच गए। उन्होंने थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान थाने के रिकॉर्ड, रजिस्टर, जरायम रजिस्टर चेक कर सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके पश्चात थाना अफजलपुर पर कांबिंग गश्त कर रही पार्टी को चेक किया। थाने के निरीक्षण के दौरान थाने पर पेंडिंग अपराधो के जल्द निकाल करवाने, इनामी एवम फरारी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु भी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया। थाने पर समुचित प्रकाश की व्यवस्था करवाने हेतु भी निर्देशित किया गया।

मंदिर में चोरी, आरोपी को दबोचा

चोरी किया गया माल व नगदी बरामद

सीतामऊ, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। ग्राम खंडेरिया काचर स्थित बालाजी मंदिर में चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा है। उसके कब्जे से चोरी का सामान भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि बीती 9-10 जून की दरमियानी रात बालाजी मन्दिर खण्डेरिया काचर से चांदी का छत्र वजनी 300 ग्राम, 1200 रूपये दानपात्र राशि, सूर्या कम्पनी का टेबल फेन अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गया था। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरु की।

पुलिस ने मामले में आरोपी इमरान पिता बाबु पठान उम्र 36 साल निवासी दाउदखेडी थाना वायडी नगर हाल मुकाम इन्द्रा कॉलोनी मन्दसौर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चांदी का छत्र, 1200 रूपये दानपात्र राशि, सूर्या कम्पनी का टेबल फेन, अपराध मे प्रयुक्त लोहे का सरिया तथा मोटर सायकल जब्त की है।

कार की टक्कर से बाईक सवार दंपती घायल

गरोठ, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। क्षेत्र के गांव कोटडा बुजुर्ग में तेज गति से आ रही कार ने बाईक सवार बगुनिया निवासी पति-पत्नि को अपनी कार से टक्कर मार दी। जिससे दंपती घायल हो गए। घायलो का नाम शाकिर खां उम्र 46 साल और फरीदा बेगम उम्र 45 साल बताए गए हैं। जिन्हें गरोठ के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर मंदसौर बड़े अस्पताल रेफर किया गया। कार क्रमांक आरजे 02 एस एफ 8083 भवानी मंडी राजस्थान की बताई जा रही है।

गरोठ थाने से सहायक उप निरीक्षक धन्नालाल जोशी ने बताया कि दोनों ही वाहनों को गरोठ थाने लाया गया है। घायलों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें रेफर किया गया है। फरियादी अभी कोई नहीं आया है। इसलिए मामला नहीं बनाया है। कोई आएगा तो आगे की कार्रवाई थाने से की जाएगी।

मंडी में भीगी किसानों की उपज, दिनभर उमस, शाम को बारिश

मंदसौर, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। अंचल में प्री मानसून की एक्टिविटी शुरु हो गई है। मंगलवार से दिन भर उमस से लोग परेशान रहे और शाम होते ही बारिश का दौर शुरु हो गया। इस दौरान मंदसौर मंडी में फसल बेचने आए किसानो की उपज भीग गई। कभी बूंदाबांदी तो कभी तेज बारिश का दौर लंबे समय तक चलता रहा। आज बुधवार को भी मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान लगाया है। इसके बाद अगले दो-तीन दिन बारिश के आसार नहीं है। इस दौरान तापमान वृद्धि होगी। मंगलवार को जिले में अधिकतम तापमान 35 डिग्री व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास बना रहा। मौसम जानकारों के अनुसार जिले में 20 जून के आसपास मानसून की एंट्री होगी। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल की सीनियर वैज्ञानिक दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से प्री-मानसून एक्टिविटी है। सोमवार को मानसून महाराष्ट्र के कई हिस्सों में पहुंचा। हालांकि, अगले दो-तीन दिन तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ब्रांच थोड़ी कमजोर होगी। ऐसे में मानसून 16-17 जून तक ही प्रदेश में एंटर हो सकेगा।

विवादित स्टेण्ड पर किसी ने लगा दी हनुमानजी की प्रतिमा

संविधान निर्माता आम्बेडकर, केन्द्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया व पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा लगाने के प्रस्ताव हुए थे पारित, विरोध के बाद इसे खाली रखने का दिया था निर्णय

पिपलियामंडी, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। रेलवे फाटक स्थित बस स्टेण्ड पर विवादित खाली पडे स्टेण्ड पर रातों-रात किसी ने भगवान हनुमान प्रतिमा की स्थापना कर दी। इसका दलित व पिछडा वर्ग नेताओं ने विरोध करते हुए तत्काल शातिभंग करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। इधर पुलिस व प्रशासन मामले में पल्ला झाडता नजर आया। जानकारी के अनुसार फाटक के पास स्थित बस स्टेण्ड पर वर्षों से खाली पडे स्टेण्ड पर बीती रात्रि किसी ने भगवान हनुमान प्रतिमा लगा दी। प्रतिमा लगने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया शुरु हो गई। किसी ने पक्ष में तो किसी ने विपक्ष में इस प्रतिक्रिया देना शुरु कर दी।

तीन कांग्रेस के नगर अध्यक्षों के कार्यकाल में अलग-अलग प्रतिमाओं के प्रस्ताव हो चुके:- जानकारी के अनुसार बस स्टेण्ड पर प्रतिमा लगाने को लेकर कांग्रेस के कार्यकाल में तीन प्रस्ताव हो चुके है। इसमें 1996 में पंडित रामप्रसाद शर्मा के कार्यकाल के दौरान यहां संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद सन् 2002-03 में कचरमल राठौर के कार्यकाल के दौरान यहां पूर्व केन्द्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ। सन् 2006 में चोथमल गुप्ता के कार्यकाल में यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ था।

विवादित होने पर मामला पहुंचा था कलेक्टर के पास, जांच में प्रकरण निरस्त कर रखा था यथावत:- सन् 2006 में यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव पारित होने पर पिछडा व दलित वर्ग ने विरोध शुरु कर दिया था, धरना, आंदोलन व रैली निकाली थी। पिछडा वर्ग नेता कचरुलाल चडावत ने इसकी शिकायत तत्कालीन कलेक्टर रही एम गीता से की थी, उस समय कलेक्टर ने एसडीएम को जांच अधिकारी नियुक्ति किया। जांच के दौरान एसडीएम ने दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा लगाने के प्रकरण को निरस्त कर स्टेण्ड को यथावत खाली रखने का आदेश दिया था। चडावत ने बताया कि भीमराव आम्बेडकर प्रतिमा के लिए आरक्षित स्टेण्ड पर रातों रात हनुमान प्रतिमा लगाकर शांतिभंग करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर शीघ्र सामाजिक न्याय मंच का प्रतिनिधि मंडल वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेगा और आन्दोलन किया जाएगा।

प्रशासन निकाल रहा नींद, बड़ी घटना के इंतजार में:- दलित नेता किशनलाल चौहान ने आरोप लगाया कि संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा के लिए आरक्षित स्टेच्यू पर रातों रात कोई व्यक्ति हनुमान प्रतिमा लगा गया। अभी तक .... शेष पेज 4 पर

विचार-मंथन

नीतीश अब राजग के 'किंगमेकर' बने

राजनीति केवल आंकड़ों का खेल नहीं, अपितु यह राजनीतिक सूझबूझ और हालात के करवट बदलने पर ठीक समय पर ठीक निर्णय लेने की कला भी है। यह अभूतपूर्व गुण बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल (यूनाइटेड) के अध्यक्ष नीतीश कुमार में विद्यमान है। 18वीं लोकसभा के चुनाव नतीजों के रुझान जैसे ही धीरे-धीरे स्पष्ट होने लगे और भारतीय जनता पार्टी '400 के पार' के दावों के विपरीत 240 पर जाकर अटक गई, तो सभी की नजरें नीतीश कुमार (जिनके 12 सांसद चुने गए हैं) और चंद्रबाबू नायडू (जिनकी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के 16 सांसद चुने गए हैं) पर टिक गईं। नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने 4 जून को यूं ही नीतीश को फोन करके राजनीतिक पासा नहीं फैंका था, क्योंकि वह भांप गए थे कि नीतीश कुमार की अब वास्तविक राजनीतिक शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। पर नीतीश कुमार और श्री नायडू ने पवार के झांसे में आने से स्पष्ट इंकार कर दिया। नीतीश कुमार वास्तव में 2024 के आम चुनाव से एक वर्ष पहले ही विपक्ष की एकता के मिशन के सूत्रधार थे और उन्होंने तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर दक्षिण भारत के दिग्गजों नवीन पटनायक, चन्द्रबाबू नायडू आदि से स्वयं जाकर मुलाकातें कीं और इस उद्देश्य के लिए उन्हें लामबंद करने हेतु अनथक यत्न किए। चुनाव के निकट आने पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ओर से विपक्ष को एकजुट करने के लिए शेष विरोधी दलों के नेताओं के साथ-साथ नीतीश से भी इसके लिए निमंत्रित किया था, तो वहां बैठकों में नीतीश कुमार के यत्नों को अनदेखा कर दिया गया। उन्हें विपक्षी गठजोड़ का संयोजक भी न बनाया गया, हालांकि वह इसके हकदार थे।

जब विपक्ष समेत कांग्रेस की ओर से बुलाई गई लगातार 2 बैठकों में नीतीश को पूरा महत्व देने की बजाय उन्हें किसी योजना के तहत जानबूझ कर दरकिनार कर दिया गया तो यह सलूक देख कर नीतीश ने ऐसी कोशिशों से किनारा कर लिया। इसके पश्चात् मोदी एवं भाजपा नेतृत्व ने नीतीश को सम्मान दिया और वह राजग में लौट आए थे। पंजाबी में कहावत है ''गौं भुनावे जौं भावें गिल्ले होन''-भाव यह कि जब राजनीतिक जरूरत हो तो गीले जौं भी भुनने के लिए स्वीकार्य होते हैं-यही हाल अब विपक्ष का है। नोट करने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी ने चुनाव परिणाम आने पर सीधे नीतीश कुमार को फोन करके सहायता मांगने की अपेक्षा यही काम अपने सहयोगी शरद पवार से कराना उचित समझा क्योंकि यह तो राहुल को भी ज्ञात था कि विपक्ष की एकता के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार को किस तरह उन्हीं की बैठकों में दरकिनार कर दिया गया था। यह अच्छा ही हुआ कि नीतीश कुमार और चन्द्रबाबू नायडू ने भी शरद पवार द्वारा 4 जून को किए गए टैलीफोनों को सुना तो जरूर मगर कोई भाव नहीं दिया। यह तो कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष को भी दिखाई दे रहा था कि आज देश की राजनीति जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां से आगे जाने हेतु खेवनहार नीतीश और चंद्रबाबू ही हैं क्योंकि इन दोनों के सामूहिक सांसदों की गिनती 28 बनती है और इसीलिए उन्होंने सोचा कि यह दोनों नेता यदि पाला बदल लें तो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोका जा सकता है। 'इंडिया' के 234 उम्मीदवार जीत चुके थे और 234+28=262 का जोड़ अब विपक्ष की नैया को पार लगाने के करीब ला सकता है। कुछ अन्य छोटे सांसदों ने भी कांग्रेस का समर्थन करने की बात कह दी थी। इस प्रकार 'इंडिया' गठजोड़ जोड़-तोड़ करके 272 के जादुई आंकड़े के पास पहुंचने की आस लगाए बैठा था। ध्यान से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेतृत्व को भी इस बात का श्रेय देना बनता है कि जब नीतीश ने विपक्ष की एकता की मुहिम में ठोकर खाई तो वह स्वतंत्र होकर राजनीति में विचर रहे थे। इसी समय मोदी ने उन्हें पूरे सम्मान सहित अपने खेमे में बुला लिया और वह राजग का हिस्सा बन गए। कहते हैं कि इतिहास अपने आपको दोहराता है। दिल्ली में जब मुगल शासक कमजोर हुए तो दिल्ली दरबार में 2 बड़े दरबारी उभरे, वह जिसे चाहते दिल्ली का बादशाह बना देते और अनचाहे बादशाह को गद्दी से उतार भी देते थे। इन भाइयों को 'बादशाह-गर भाई' (किंगमेकर-बादशाह बनाने वाले) के नाम से जाना जाता है। किसी समय ऐसी ही शक्ति कश्मीरी पंडितों के पास भी थी।

सेंट्रल हाल से संदेश क्या पांच साल के लिए है?

अजय सेतिया

पुराने संसद भवन का नया नाम अब संविधान सभा है। जहां संविधान सभा की बैठक हुआ करती थीं, उसे हम पिछले 75 साल से सेंट्रल हाल के रूप में जानते हैं। यह सेंट्रल हाल 75 साल से लोकतंत्र के हर उतार चढ़ाव का गवाह रहा है। इस सेंट्रल हाल में ही सरकारों के बनने और गिरने की पटकथा लिखी जाती रही है। जब देश में कांग्रेस का बोलबाला था, तब चुनाव के बाद कांग्रेस संसदीय दल की बैठक यहीं पर होती थी, यहीं पर नए प्रधानमंत्री के नाम पर मोहर लगती थी। अब एनडीए का बोलबाला है, तो इसी सेंट्रल हाल में एनडीए ने नरेंद्र मोदी को चुनने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया। कांग्रेस के जमाने और मौजूदा दौर में फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में पत्रकारों को आने की इजाजत होती थी, जो अब बंद हो चुकी है। सेंट्रल हाल क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मन्दिर था, इसलिए मीडिया इस सेंट्रल हाल की रोजमर्रा की गतिविधियों का साक्षी हुआ करता था, जो अब नहीं है। इस सेंट्रल हाल में कुछ बदला है तो सिर्फ यही बदला है कि लोकतंत्र का खुलापन सिकुड़ गया है, अठारहवीं लोकसभा के चुनाव नतीजों के बाद जिसके खुलने की उम्मीद की जा सकती है। 2004 में इसी सेंट्रल हाल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था। हालांकि यह फैसला सोनिया गांधी के घर पर हुई यूपीए के घटक दलों की बैठक में ही हो चुका

था, लेकिन कांग्रेस में जो परिवार भक्ति और मान-मनोव्वल की परंपरा रही है, उसका सबके सामने प्रदर्शन हुआ। उसके विपरीत सात जून 2024 को एनडीए ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में अपना नेता चुनने की प्रक्रिया पूरी की। पिछली दो सरकारों के विपरीत इस बार भाजपा के बहुमत वाली सरकार नहीं बन रही। इसलिए चंद्रबाबू नायडू , नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान को ज्यादा अहमियत मिली। यहाँ तक कि कुछ पार्टियों के अकेले सांसद जीतन राम मांझी, अनुप्रिय पटेल और अजीत पवार को भी उतनी ही अहमियत दी गई, ताकि कोई एक बड़ा दल खिसक जाए, तब डूबते को तिनके का ही सहारा होता है। नतीजे आने के तुरंत बाद से ही मीडिया का एक वर्ग चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को शक की निगाह से देख रहा था। भाजपा नेताओं राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी की ओर से मोदी को नेता चुनने का प्रस्ताव रखे जाने के बाद सबसे पहले लोकसभा की 16 सीटें जीतने वाले टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और 12 सीटें जीत कर लाने वाले जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार से अनुमोदन करवाया गया, यह जरूरी भी था। क्योंकि ये दोनों ही पहले नरेंद्र मोदी से नाराज हो कर एनडीए छोड़ कर चले गए थे, और दोनों ही यूपीए का हिस्सा भी रह चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू ने 2019 के लोकसभा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों से ठीक पहले एनडीए छोड़ दिया था, और एनडीए सरकार के खिलाफ दिल्ली के आंध्र भवन में एक दिन का धरना दिया था। धरने पर सोनिया गांधी, सीताराम येचुरी और डी. राजा भी शामिल हुए थे। लेकिन एनडीए का साथ छोड़कर वह आंध्र प्रदेश विधान सभा का चुनाव तो बुरी तरह हारे ही, लोकसभा में भी उनका कद घट गया था। पिछले दो साल से वह दुबारा एनडीए में आने की कोशिश कर रहे थे, चुनावों से ठीक पहले उन्हें एनडीए में एंट्री मिली थी, और एनडीए में आते ही उनकी किस्मत का दरवाजा भी खुल गया। वह भारी बहुमत के साथ फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं, और नरेंद्र मोदी सरकार भी उनपर निर्भर हो गई है। वह चित्र लोगों के जहन में अभी भी होगा, जब नीतीश कुमार ने चुनावों में एक रैली के दौरान मंच पर नरेंद्र मोदी के पाँव छूने की कोशिश की थी। यह उनका एनडीए छोड़कर जाने का पछतावा था, जो उन्हें झुका रहा था। वह दो बार एनडीए छोड़कर लालू यादव और कांग्रेस के साथ गए थे। दोनों ही बार उन्हें कड़वा अनुभव हुआ, तो उन्हें लौट कर एनडीए में आना पड़ा। चुनावों के दौरान ही एक बार उन्होंने मंच पर सार्वजनिक तौर पर अपनी गलती को स्वीकार किया और मोदी से वायदा किया कि अब वह कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। लगभग वैसा ही आश्वासन नीतीश कुमार ने सेंट्रल हाल में भी दिया है। लेकिन क्योंकि इन दोनों का पलटू राम का इतिहास रहा है। दोनों के अपने एजेंडे भी हैं, इसलिए मीडिया के एक वर्ग को यह खबर चलाने में आसानी रहती है कि दोनों ने समर्थन के लिए कड़ी शर्तें लगा दी हैं, दोनों ने मोलभाव शुरू कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर पद मांग लिया है, नीतीश कुमार ने रेलवे मंत्रालय मांग लिया है, आदि आदि। इन खबरों का आधार क्या है? इन अटकलबाजियों का आधार सिर्फ यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में चंद्रबाबू नायडू ने 1998 में समर्थन के बदले अपनी पार्टी के जीएमसी बालयोगी को स्पीकर बनवाया था और नीतीश कुमार वाजपेयी सरकार में रेलमंत्री थे। लेकिन इस बार ये दोनों ही कड़वे अनुभव के बाद एनडीए में लौटे हैं, और इन दोनों के एजेंडे पर इस बार अपने सांसदों को महत्वपूर्ण पद या मंत्रालय दिलाना नहीं, अपने अपने राज्य हैं। दोनों ही अपने अपने राज्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग जरूर करेंगे और मोदी सरकार को इसका रास्ता निकालना ही होगा। संविधान का अनुच्छेद 370 और 371 कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देता है, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को मिलने वाला विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था। लेकिन अनुच्छेद 371 के तहत पूर्वोत्तर और कुछ अन्य पहाड़ी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा है, जिसमें उनको केंद्र से विशेष आर्थिक मदद मिलती है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपने अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे हैं। कोई भी केंद्र सरकार नहीं चाहेगी कि दो राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देकर बाकी राज्यों को भड़काने का काम किया जाए, सवाल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की ओर से पांच साल की गारंटी का है। राजनीति में कब क्या हो जाए, इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, लेकिन सेंट्रल हाल में इन दोनों की बॉडी लेंग्वेज पांच साल की गारंटी वाली थी।

देश को मजबूत सरकार की जरूरत क्यों

हर्ष रंजन

जापान, वर्ष 2010 तक करीब 5 दशकों तक संयुक्त राज्य अमरीका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बना रहा था। फिर वह तीसरे स्थान पर फिसल गया क्योंकि चीन ने दूसरा स्थान हासिल कर लिया और फिर अगले 13 वर्षों के अंतराल में वर्ष 2023 में जापान जी.डी.पी. के मामले में चौथे स्थान पर आ गया क्योंकि जर्मनी ने उसे धकेल कर तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया। दूसरी ओर भारत ने निरंतर विकास की कहानी देखी और काफी नीचे से ऊपर चलते हुए दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और जल्दी ही जापान को 5वें स्थान पर धकेलते हुए चौथे स्थान पर पहुंचने के लिए भारत तैयार है। जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय शिंजो आबे अपनी आक्रामक विदेश नीति और एक विशिष्ट आर्थिक रणनीति के लिए जाने जाते थे, जिसे लोकप्रिय रूप से 'एबेनॉमिक्स' के नाम से जाना जाता है। बेहद लोकप्रिय और बेहद विवादास्पद राजनेता रहे आबे ने लिबरल डैमोक्रेटिक पार्टी (एल.डी.पी.) को 2 बार जीत दिलाई। एबेनॉमिक्स श्री ऐरोज यानी 'तीन तीरों' पर केन्द्रित था। पहला आक्रामक मौद्रिक नीति, दूसरा राजकोषीय समेकन और तीसरा विकास रणनीति। जबकि पहले 2 से बेहतर परिणाम मिले, लेकिन विकास और आधारभूत परिवर्तनों के पैमाने विफल रहे क्योंकि रणनीतिकारों ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि जापानी अर्थव्यवस्था बढ़ती आबादी और बढ़ते सामाजिक कल्याण खर्चों का सामना कर रही है। यहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच सामने आती है। जब उन्होंने जन-धन खातों के माध्यम से वित्तीय समावेशन किया, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दर्जनों योजनाएं लांच कीं, युवाओं में सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए स्टार्टअप और कौशल विकास पर जोर दिया तो दरअसल वह लांग टर्म के विकास के लिए नहीं, उन पहलुओं को पहले से ही संबोधित करना चाह रहे थे जहां जापान उतना सफल नहीं हो पाया था। भारत की आबादी की औसत आयु 30 साल से भी कम है, लगभग 29.5 वर्ष। लेकिन आने वाले वर्षों में भारत की आबादी की आयु बढ़ेगी। उम्मीद है कि 2050 तक भारतीय जनसंख्या की औसत आयु लगभग 39 वर्ष होगी। वर्ष 2000 में जापानी आबादी की औसत आयु इतनी ही थी। यहीं पर पिछले 10 सालों से चल रहा देश का विजन सामने आता है। इन वर्षों में देश की सोच और दृष्टि आमतौर पर लंबी अवधि के लिए रही है। भारत 2047 तक पूरी तरह से विकसित राष्ट्र बनने की योजना बना रहा है, जब हम आजादी के 100 साल मनाएंगे, तो योजना बनाना और ऐसे रुख अपनाना जरूरी है जो भले ही अजीब और अनूठे लग सकते हैं, लेकिन समय आने पर इसके परिणाम मिलेंगे और जापान की कहानी नहीं दोहराई जाएगी। इसके बिल्कुल विपरीत, जापान की अर्थव्यवस्था की कहानी सतर्कता की घंटी बजाती है। एक समय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा जापान संयुक्त राज्य अमरीका, चीन और जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर खिसक गया है। पर्याप्त सरकारी प्रयासों और मौद्रिक प्रोत्साहन के बावजूद, जापान की आबादी की बढ़ती उम्र ने इसकी आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक संरचनात्मक और शासन सुधारों में बाधा उत्पन्न की है। यह जनसांख्यिकीय चुनौती आर्थिक नवाचार और विकास को आगे बढ़ाने में युवा नेतृत्व के महत्वपूर्ण महत्व को बताती है। युवा नेतृत्व पर देश का जोर महज एक राजनीतिक रणनीति नहीं है बल्कि भारत के भविष्य के लिए एक रणनीतिक अनिवार्यता है। युवा नेता नए दृष्टिकोण, नवीन समाधान और एक मजबूत ऊर्जा लाते हैं जो शासन और नीति-निर्माण प्रक्रियाओं को पुनर्जीवित कर सकते हैं। सम-सामयिक तकनीकी प्रगति और वैश्विक रुझानों से उनकी निकटता उन्हें तेजी से विकसित हो रही दुनिया की जटिलताओं से निपटने में सक्षम बनाती है। उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में युवा नेताओं को शीर्ष पर रखकर एक ऐसी शासन संस्कृति देश में आ रही है जो चुस्त, उत्तरदायी और दूरदर्शी है। ऐसा नहीं है कि यह काम सत्ता पक्ष ने ही किया है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, भजनलाल शर्मा, पुष्कर धामी और मोहन यादव आदि हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव का उभरना पार्टी राजनीति से ऊपर की बात है।

मोदी के बाद योगी ने खूब बहाया पसीना

73 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी ने कितना पसीना बहाया, इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अकेले 206 चुनावी रैलियां की या रोड शो किए। पूर्वोत्तर भारत के कुछ-एक इलाकों को छोड़ दें तो तकरीबन समूचे देश में उन्होंने रैली और रोड शो नहीं किया है। आम चुनाव के नतीजों की उलटी गिनती शुरू हो गई है। अगर नतीजे एक्जिट पोल जैसे ही रहते हैं तो मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है। यूं तो हर जीत का सेहरा सेनापति के ही सेहरे पर बंधता है। नरेंद्र मोदी बीजेपी के हरावल दस्ते के अगुआ हैं, इसलिए निःसंदेह मौजूदा जीत उनकी ही होगी। लेकिन इस जीत के बीजेपी की ओर से कई और नायक भी हैं। मोदी और अमित शाह की जोड़ी को भारतीय राजनीति की सबसे सफल जोड़ी की प्रतिष्ठा हासिल हो चुकी है। जाहिर है कि इस जीत के नायक अमित शाह भी हैं। लेकिन बीजेपी के तीसरी बार सत्तारोहण में एक और शख्स की मेहनत भी शामिल है। ये शख्स हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अठारहवीं लोकसभा के चुनाव को लेकर बीजेपी ने जबरदस्त मेहनत की। उसने बेहतर रणनीति बनाई। चुनावी मैदान पर वोटरों को लुभाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। 73 साल की उम्र में उन्होंने कितना पसीना बहाया, इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अकेले 206 चुनावी रैलियां की या रोड शो किए। पूर्वोत्तर भारत के कुछ-एक इलाकों को छोड़ दें तो तकरीबन समूचे देश में उन्होंने रैली और रोड शो नहीं किया है। भारत में अगर 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोटिंग किया है, उन्हें मतदान केंद्रों तक बुलाने में राजनीतिक दलों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसमें सबसे बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री मोदी की रही है। दिलचस्प यह है कि बीजेपी की ओर से लोगों को लुभाने के लिए जिन नेताओं ने मेहनत की है, उनमें दूसरे नंबर पर अगर कोई है तो वे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने देशभर में करीब 197 रोड शो और रैलियां की हैं। बीजेपी के चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ की मांग उत्तर प्रदेश में रहनी थी। वैसे उत्तर प्रदेश में पार्टी को जिताना उनकी जिम्मेदारी भी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर भी उनकी खूब मांग रही। योगी जी ने उत्तर प्रदेश से बाहर बारह राज्यों उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जम्मू, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ओडिशा, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली जैसे बारह राज्यों में उन्होंने प्रचार किया। योगी को लेकर देश का कथित प्रबुद्ध वर्ग विरोधी भाव रखता है। लेकिन चुनाव अभियान में प्रबुद्ध लोगों को लुभाने के लिए उन्होंने प्रबुद्ध लोगों की पंद्रह सभाओं को भी संबोधित किया। मौजूदा चुनाव अभियान जैसे शुरू हुआ था, एक अफवाह फैलाई गई कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी जीती तो योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। चुनाव अभियान के दौरान बीजेपी के प्रति क्षत्रिय समुदाय के गुस्से की भी अफवाहें फैलीं। बीजेपी ने शुरू में तो इन अफवाहों पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन बाद में जब पार्टी को लगा कि इस अफवाह का नुकसान हो सकता है तो पार्टी को सामने आना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी को कई सभाओं में योगी की तारीफ करनी पड़ी। अलीगढ़ की सभा में 23 अप्रैल को मोदी ने जो कहा, उससे पार्टी में योगी की महत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है। तब मोदी ने कहा, जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के काल खंड में हुआ है।

12 जून अन्तर्राष्ट्रीय बालश्रम विरोधी दिवस पर विशेष......

सामाजिक सरोकार की कमी से बढ़ रही है बाल मजदूरी की कुप्रथा, कानून से नहीं, जागरूकता से अंकुश लगेगा

मंदसौर, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। हम लोग बहुत समय से ''बालश्रम'' के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान का हिस्सा बनकर लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले मैंने जब वर्ष 1995 से बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता एवं अंतराष्ट्रीय बाल अधिकार कार्यकर्ता श्री कैलाश जी सत्यार्थी के साथ कार्य करना प्रारम्भ किया था तब मुझे लग रहा था कि ''बलश्रम'' जैसी गम्भीर समस्या से सिर्फ हमारा देश ही जूझ रहा है लेकिन जब बचपन बचाओ आंदोलन के माध्यम से मुझे भारत के साथ साथ अन्य देशों की स्थिति जानने का अवसर मिला तो मुझे महसूस हुआ कि बालश्रम की समस्या तो वैशविक समस्या है और इस गम्भीर समस्या ने तो पूरी दुनिया में ही पैर जमा लिए है।

कुछ लोग मुझे कहते है कि बच्चे काम नहीं करेंगे तो भूखे मर जायेंगे लेकिन उनके पास मेरे सवालों का जवाव नहीं होता है कि जब तक बच्चों से काम कराया जावेगा तब तक वयस्कों के रोजगार पर डाका पड़ता रहेगा। वर्त्तमान दौर में बाजार के वैश्वीकरण तथा बड़े लोंगों के धन एकत्र करने की लोलुपता के कारण बाल मजदूरों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। खतरनाक और गैर खतरनाक उद्योगों में जहा लगभग भारत में द्धन्त्र करोड़ बच्चे तिल तिल कर मजदूरी करने को विवस है तो वही दूसरी ओर घरों की चार दीवारों के बीच भी नाबालिग लड़कों एवं लड़कियों से बडी संख्या में मजदूरी कराई जा रही है।

सामाजिक सरोकार की कमी के कारण बाल मजदूरों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और हम सब मूक दर्शक बन कर तमाशा देख रहे है। यह माना जाता है कि भारत में 14 साल के बच्चों की आबादी पूरी अमेरिकी आबादी से भी ज़्यादा है. भारत में कुल श्रम शक्ति का लगभग 3.6 फीसदी हिस्सा 14 साल से कम उम्र के बच्चों का है. हमारे देश में हर दस बच्चों में से 9 काम करते हैं। ये बच्चे लगभग 85 फीसदी पारंपरिक कृषि गतिविधियों में कार्यरत हैं, जबकि 9 फीसदी से कम उत्पादन, सेवा और मरम्मती कार्यों में लगे हैं। सिर्फ 0.8 फीसदी कारखानों में काम करते हैं। आमतौर पर बाल मज़दूरी अविकसित देशों में व्याप्त विविध समस्याओं का नतीजा है। भारत सरकार दूसरे देशों के सहयोग से बाल मज़दूरी ख़त्म करने की दिशा में तेज़ी से प्रयासरत है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) जैसे महत्वपूर्ण क़दम उठाए हैं। आज यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस परियोजना ने इस मामले में काफी अहम कार्य किए हैं। इस परियोजना के तहत हज़ारों बच्चों को सुरक्षित बचाया गया है। साथ ही इस परियोजना के तहत चलाए जा रहे विशेष स्कूलों में उनका पुनर्वास भी किया गया है। इन स्कूलों के पाठ्यक्रम भी विशिष्ट होते हैं, ताकि आगे चलकर इन बच्चों को मुख्यधारा के विद्यालयों में प्रवेश लेने में किसी तरह की परेशानी न हो। ये बच्चे इन विशेष विद्यालयों में न सिर्फ बुनियादी शिक्षा हासिल करते हैं, बल्कि उनकी रुचि के मुताबिक़ व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत इन बच्चों के लिए नियमित रूप से खानपान और चिकित्सकीय सहायता की व्यवस्था है। साथ ही इन्हें एक सौ रुपये मासिक वजीफ़ा दिया जाता है।

ग़ैर सरकारी संगठनों या स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे ऐसे स्कूल इस परियोजना के अंतर्गत अपना काम अगर निष्ठा एवं ईमानदारी से करें तो हज़ारों बच्चे मुख्य धारा में शामिल हो सकते है। लेकिन अभी भी देश में करोड़ों बच्चे बाल मज़दूर की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। समाज की बेहतरी के लिए इस बीमारी को जड़ से उखाड़ना बहुत ज़रूरी है। एनसीएलपी जैसी परियोजनाओं के सामने कई तरह की समस्याएं हैं। यदि हम सभी इन समस्यायों का मूल समाधान चाहते हैं तो हमें इन पर गहनता से विचार करने की ज़रूरत है। इस संदर्भ में सबसे पहली ज़रूरत है 14 साल से कम उम्र के बाल मज़दूरों की पहचान करना।

आख़िर वे कौन से मापदंड हैं, जिनसे हम 14 साल तक के बाल मज़दूरों की पहचान करते हैं और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मान्य हों? क्या हमारा तात्पर्य यह होता है कि जब बच्चा 14 साल का हो जाए तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी राज्य की हो जाती है? हम जानते हैं कि ग़रीबी में अपना गुज़र-बसर कर रहे बच्चों को परवरिश की ज़रूरत है। कोई बच्चा जब 14 साल का हो जाता है और ऐसे में सरकार अपना सहयोग बंद कर दे तो मुमकिन है कि वह एक बार फिर बाल मज़दूरी के दलदल में फंस जाए। यदि सरकार ऐसा करती है तो यह समस्या बनी रह सकती है और बच्चे इस दलदल भरी ज़िंदगी से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। कुछ लोगों का मानना है और उन्होंने यह प्रस्ताव भी रखा है कि बाल मज़दूरों की पहचान की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 18 साल कर देनी चाहिए। साथ ही सभी सरकारी सहायताओं मसलन मासिक वजीफ़ा, चिकित्सा सुविधा और खानपान का सहयोग तब तक जारी रखना चाहिए, जब तक कि बच्चा 18 साल का न हो जाए। कई सरकारें बाल मज़दूरों की सही संख्या बताने से बचती हैं। ऐसे में वे जब विशेष स्कूल खोलने की सिफारिश करती हैं तो उनकी संख्या कम होती है, ताकि उनके द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों और कार्यकलापों की पोल न खुल जाए। यह एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है और आज ज़रूरत है कि इन सभी मसलों पर गहनता से विचार किया जाए।

मौजूदा नियमों के मुताबिक़, जब बच्चा मुख्य धारा के स्कूलों में दाख़िला ले लेता है तो ऐसा माना जाता है कि मासिक सहायता बंद कर देनी चाहिए. जबकि बच्चे या उसके माता-पिता नहीं चाहते हैं कि वित्तीय सहायता बंद हो। ऐसे में उनका अकादमिक प्रदर्शन नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। यही वजह है कि हर कोई सोचता है कि जब बच्चा मुख्य धारा के स्कूल में प्रवेश कर जाए तो उसके बाद भी उसे सहायता मिलती रहनी चाहिए। आख़िरकार अतिरिक्त पैसे के लिए ही तो माता-पिता अपने बच्चों से मज़दूरी करवाते हैं। इसीलिए किसी भी तरह आर्थिक सहायता जारी रहनी चाहिए. यह तब तक मिलनी चाहिए, जब तक कि वह बच्चा पूर्ण रूप से मुख्य धारा में शामिल होने के क़ाबिल न हो जाए. हालांकि पुनर्वास पैकेज की पूरी व्यवस्था की गई है, फिर भी बच्चे के माता-पिता सरकारी सुविधाओं के हक़दार नहीं माने गए हैं. ऐसे में हर किसी को यह लगता है कि इस संदर्भ में एक सामान्य नियम होना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों के लिए एक विशेष वर्ग निर्धारित हो सके। जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, सैनिकों की विधवाओं, पूर्व सैनिक और अपाहिज लोगों के लिए एक अलग वर्ग निर्धारित किया जा चुका है।

बाल मज़दूरी ख़त्म करने और व्यवसायिक प्रशिक्षण का लक्ष्य हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें उपर्युक्त पहलुओं को समझना बेहद ज़रूरी है. व्यवसायिक प्रशिक्षण के दौरान जिन उत्पादों का निर्माण होता है, उनका विपणन यदि ठीक ढंग से हो तो उसकी लागत पर आने वाले ख़र्च को हासिल किया जा सकता है. लेकिन यह सब परियोजना विशेष, उसके विस्तार और उत्पाद की गुणवत्ता पर निर्भर करता है. साथ ही यह परियोजना का कार्यान्वियन करने वाले व्यक्तिपर भी निर्भर करता है कि वह इन सबका प्रचार-प्रसार ठीक ढंग से कर पा रहा है या नहीं. यह देखने में आया है कि बाल मज़दूरी रोकने संबंधी नियम बन चुके हैं, लेकिन अभी भी इसे ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया है. बाल मज़दूरी को बढ़ावा देने वाले ख़ुद समाज के ग़रीब तबके से आते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को हिरासत में लेने या दंडित करने के प्रति भी हमारी कोई रुचि नहीं दिखती. जहां लोग बाल मज़दूरी से परिचित होते हैं, वे इस अपराध से बच निकलने में सफल हो जाते हैं. अत: हमें यहां सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि बाल श्रम अधिनियम (निषेध एवं विनियमन) को सही मायनों में लागू किया जा रहा है या नहीं. यह भी देखा जा रहा है कि जिन बाल मज़दूरों को मुक्त कराया जाता है, उनका पुनर्वास जल्द नहीं हो पाता, नतीजतन वे फिर इस दलदल में फंस जाते हैं. ऐसे में हमें इसके ख़िलाफ कड़े क़दम उठाने की आवश्यकता है. साथ ही 20 हजार रुपये की राशि एक बाल मज़दूर के पुनर्वास के लिए बेहद ही मामूली राशि है, जिसे बढ़ाए जाने की भी ज़रूरत है. ज़मीनी स्तर पर पुनर्वास को सही ढंग से लागू करने के लिए वित्तीय सहायता के साथ-साथ एक बेहतर पुनर्वास ख़ाका भी बनाया जाना चाहिए. कई सरकारें बाल मज़दूरों की सही संख्या बताने से बचती हैं. ऐसे में वे जब विशेष स्कूल खोलने की सिफारिश करती हैं तो उनकी संख्या कम होती है, ताकि उनके द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों और कार्यकलापों की पोल न खुल जाए।

यह एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है और आज ज़रूरत है कि इन सभी मसलों पर गहनता से विचार किया जाए. यदि सरकार सही तस्वीर छुपाने के लिए कम संख्या में ऐसे स्कूलों की सिफारिश करती है तो यह नियमों को लागू करने एवं बाल श्रमिकों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की दिशा में एक गंभीर समस्या और बाधा है. जब तक पर्याप्त संख्या में संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, ऐसी समस्याओं से निपटना मुश्किल ही होगा. यहां बाल श्रम से निपटने की दिशा में न सिर्फ नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है, बल्कि इसके लिए कार्यरत विभिन्न परियोजनाओं को वित्तीय सहायता आवंटित करने की भी ज़रूरत है. कुछ मामलों में बाल श्रमिकों की पहचान की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इन परियोजनाओं में कुछ बुनियादी संशोधन की आवश्यकता ज़रूर है. इस देश से बाल मज़दूरी मिटाने के लिए अधिक समन्वित और सहयोगात्मक रवैया अपनाने की सख्त आवश्यकता है।

आप और हम यह कर इस संख्या को कम करने में अपना योगदान दे सकते है :- ✻हम सब मिलकर बाल मजदूरी जैसे जघन्य अपराध के विरुद्ध लोंगों को जाग्रत करे। ✻ अपने घरो, दफ्तरों, दुकानों में बच्चों से काम न करवाये एवं जहां बच्चों से काम कराया जाता हो उन संस्थानों, दुकानों, होटलों का बहिष्कार करे। ✻ बालश्रम से बनाये गए उत्पादों का बहिष्कार करें। ✻ अगर आपके आस पास कही भी किसी प्रकार का श्रम बच्चों से कराया जा रहा है तो उसकी शिकायत तत्काल पुलिस, श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति या बाल अधिकार और मानवाधिकार आयोग को करें। ✻ यह सब कार्य कर हम 'स्टॉप चाइल्ड लेबर'' अभियान में सहभागी बन कर बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने में सहभागी बन सकते है।

डॉ राघवेन्द्रसिंह तोमर
बाल अधिकार एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता

शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करें-कलेक्टर

जनसुनवाई में सुनी 68 आवेदकों की समस्याएं, निराकरण के निर्देश

नीमच, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। जिले के सिंगोली पटवारी द्वारा निजी खाता भूमि की दुर्भावनावश गलत चर्तु सीमा लिखकर बगैर कब्जा के विक्रय पत्र कराने, गलत प्रतिवेदन, नजरी नक्शा, पंचनामा प्रस्तुत करने संबंधी शिकायत की जांच कर एसडीएम जावद रिर्पोट प्रस्तुत करें। रीडर, प्रकरण दर्ज कर उभय पक्षों को आहूत करें और पटवारी से वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन प्राप्त करें। यह निर्देश कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने मंगलवार को कलेक्टोरेट में जनसुनवाई करते हुए सिंगोली निवासी नवीन पिता अनिल कुमार तिवारी के आवेदन पर एसडीएम जावद व रीडर को दिए। इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद, एडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री जैन ने ग्राम जाट निवासी बरकत अली की ग्राम जाट के कुछ ग्रामीणों व्दारा लगभग 15 बीघा शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करने संबंधी शिकायत पर राजस्व प्रकरण दर्ज कर, तहसीलदार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में कलेक्टर श्री जैन ने 68 आवेदकों की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण करने के निर्देश संबंधित जिला अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई में स्कीम नम्बर 9 के यशवंत यादव, ग्राम कुचडौद के श्यामलाल रावत, पांडुकुडी की सज्जीबाई, विकास नगर की भागवंती, यादव कम्यूनिटी सेंटर समिति के चंदनसिह हरित, विनो बागंज की दीपमाला, ग्वालटोली की रूपाबाई, पिपलिया नाथावत के रतनसिह, हनुमंतिया के फुलचंद, केलुखेडा के समरथ, ग्वालटोली के कैलाशचंद्र, इंदिरा नगर के देवीलाल, डिकेन के रमेशचंद्र, अरनिया के घीसालाल, जमुनियाकलां के पप्पुलाल, रामपुरा के विनोद, सिंगोली के पंकज ने भी अपनी समस्या ओं से संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिये 31 जुलाई तक करें आवदेन

मंदसौर, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रय बाल पुरस्कार उन बच्चों को दिये जायेगें, जिन्होंने बहादुरी, खेलकूद, सामाजिक कार्य, विज्ञान एवं तकनीकी खेल, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया हो। उक्त पुरस्कार हेतु ऑनलाईन आवेदन https://awards.gov.in पर 31 जुलाई 2024 तक कर सकते है। अधिक जानकारी के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग में सम्पर्क कर सकते है।

जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक कल

मंदसौर, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल ने बताया कि आगामी त्यौहार ईदुज्जुहा, चौकी धुलाई, मोहर्रम, श्रावण मास, श्रावण सोमवार, शाही सवारी आदि पर्व परंपरागत रूप से शांतिपुर्वक मनाये जाने के सबंध में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक 13 जून को पुलिस कंट्रोल रूम में सभाकक्ष में सायं 5 बजे आयोजित होगी।

जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक मत्याखेट पर प्रतिबंध रहेगा

नीमच, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। म.प्र.राज्य में नदीय मत्याखे उद्योग नियम 1972 की धारा (3)(2) के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (मत्स्य प्रजनन काल) घोषित किया गया है। इस अवधि में जिले में मत्या तक खेट, मत्स्य विक्रय, मत्स्य विनिमय एवं मत्स्य परिवहन करना निषेध है। कलेक्टर श्री दिनेश जैन व्दारा जारी आदेशानुसार मध्यप्रदेश शासन मछली पालन विभाग के निर्देशानुसार छोटे तालाब अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हे निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है को छोडकर समस्त नदियों व जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्त नियमों के उल्लंघन पर म.प्र. मत्स्य क्षेत्र संशोधन अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष तक का कारावास या 5000/- रूपये अक्षरी पांच हजार रु. तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

निजी विद्यालयों व्दारा अभिभावकों के साथ किए जा रहे शोषण पर रोक लगाई जाए -ग्राहक पंचायत

मंदसौर, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मंदसौर को अभिभावकों से इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि जिले के निजी विद्यालयों द्वारा प्रकाशकों से सांठगांठ करके खुले आम विद्यार्थियों और अभिभावकों का शोषण किया जा रहा है। निजी विद्यालयों के द्वारा अभिभावकों क़ो एक ही चयनित दुकान से पुस्तक, ड्रेस व जूते मोज़े खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है इन सभी समस्याओ क़ो लेकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने प्रदेशभर में एक साथ ज्ञापन दिया। मन्दसौर में जनसुनवाई में नायब तहसीलदार रमेश् मसारे को ज्ञापन सौपा, ज्ञापन के माध्यम के माध्यम से प्रशासन से बिंदुवार मांग की..

1) विद्यालयों द्वारा अभिभावकों को नियम विरुद्ध रूप से, NCERT की पुस्तकों के स्थान पर निजी प्रकाशकों की पुस्तकें क्रय करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिसके कारण अभिभावकों को छोटी-छोटी कक्षाओं के बच्चों के पाठ्यक्रम की पुस्तकें हजारों रुपयों में

क्रय करना पड रही हैं। विद्यालयों द्वारा अभिभावकों को अत्यधिक संख्या में पुस्तकें क्रय करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिसके कारण छोटे-छोटे विद्यार्थियों के बस्तों का वजन शासन द्वारा निर्धारित वजन से बहुत अधिक हो गया है। इसके कारण अभिभावकों के मानसिक एवं आर्थिक शोषण के साथ-साथ बच्चों का मानसिक और शारीरिक शोषण हो रहा है और बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास बाधित हो रहा है। 2) निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावकों को विद्यार्थियों की ड्रेस सामग्री निश्चित दुकान से ही खरीदने का दबाव बनाया जाता है जिससे इन तय दुकान द्वारा बाजार में एकाधिकार होने से मनमाने रेट पर ड्रेस का विक्रय किया जा रहा है! 3) निजी विद्यालयों द्वारा प्रत्येक वर्ष छात्रों की फीस को नियम विरुद्ध रूप से बढाया जा रहा है, जिससे अभिभावकों की जेब पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ रहा है! शिक्षा विभाग द्वारा केवल खानापूर्ति के लिए इस सम्बन्ध में जाँच दल बनाये गये हैं जो सारी वास्तविकता जानते हुए भी किसी भी विद्यालय के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। अत: अ.भा.ग्राहक पञ्चायत मंदसौर इकाई इस ज्ञापन के माध्यम से आपसे माँग करती है कि विद्यालयों द्वारा किये जा रहे इस शोषण को रोकने के लिए सच्चाई सामने लाने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा बनाये गये जाँच दलों में ग्राहक पञ्चायत के कार्यकर्ताओं को भी सम्मिलित किया जाए और शोषण करने वाले विद्यालयों, प्रकाशकों और विक्रेताओं के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करने का कष्ट करें। इस ज्ञापन से दो दिन पहले ग्राहक पंचायत मंदसौर इकाई ने शहर के विभिन्न हिस्सों में व्यापक हस्ताक्षर अभियान चलाया था जिसमे 300 से अधिक अभिभावकों का समर्थन प्राप्त हुआ। ज्ञापन के साथ आमजन में हस्ताक्षर की सूची व अभियान के चित्र की प्रति भी सलग्न की। ज्ञापन देते समय ग्राहक पंचायत के जिलाध्यक्ष नवनीत शर्मा, जिला सचिव विजय कोठारी, जिला विधि प्रमुख उमराव सिंह जैन, जिला उपाध्यक्ष भूपेंद्र बैरागी, मिथुन वप्ता एवं अंशुल जैन उपस्थित थे।

जल संरक्षण को लेकर चित्रकला प्रतियोगिताएं सम्पन्न

नीमच, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। जल गंगा सर्वधन अभियान के अंतर्गत मप्र जन अभियान परिषद जिला नीमच के जिला समन्वयक वीरेन्द्र सिंह ठाकुर एवं ब्लॉक समन्वयक महेन्द्रपाल सिंह भाटी के मार्गदर्शन में जल संरक्षण को लेकर नवांकुर संस्था हेल्पिंग हैंडसोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जल संरक्षण विषय पर सिंगोली मे चित्रकला प्रतियोगिता करवाई। इस दौरान संस्था के विश्वास खंडेलवाल,शिव शर्मा ने जल संरक्षण पर जागरूकता शपथ भी करवाई। ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति बालागंज में स्कूल बच्चों के साथ चित्रकला का आयोजन किया गया और बच्चों को जल संरक्षण के बारे में संस्थाक प्रभारी नरेन्द्र सिंह चौहान द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। नवांकुर संस्था नीमच सुरेश लोक शिक्षण समिति द्वारा जल संरक्षण विषय पर ग्राम नेवड में बालिकाओं की चित्रकला प्रतियोगिता करवाई। जिसमें कुमारी तनुजा बैरागी राधा बैरागी दीपिका खाती बीरा खातीभाबिका मालवीय वंशिका खाती आयुषी खाती संजना बैरागी हर्षिता खाती पूनम सोलंकी निधि का दमामी राखी दमामी तथा बालक कुणाल दमामी मैं भाग लिया प्रतियोगिता का निर्णय ग्राम की महिलाओं द्वारा करवाया गया जिसमें प्रथम स्थान संजना बैरागी तथा द्वितीय स्थान कुणाल दमामी तृतीय स्थान तनुजा बैरागी एवं सांत्वना पुरस्कार राखी दमामी ने प्राप्त किया इस दौरान संस्था कोषाध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के धीरज बैरागी सहित समिति सदस्य उपस्थित रहे।

चित्रकला रंगोली पर निबंध प्रतियोगिता संपन्न- जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जीरन नगर परिषद द्वारा जल की हर बूंद बचाना है, हर जल स्त्रोत को स्वच्छ बनाना है उद्देश्य को लेकर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत तालाब की सफाई की गई। नगर परिषद कार्यालय मे स्कूली बच्चों द्वारा रंगोली,चित्रकला,निबंध प्रतियोगिता का आयोजित की गई। जिसमें प्रथम और व्दितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद के अध्यक्ष श्री रामकरण सगवारिया न.प.उपाध्यक्ष श्री मुकेशराव तावरे, पार्षद प्रतिनिधि श्री किशन अहिरवार, श्री दिलीप सुथार, श्री राजेश लक्षकार, श्री हरिओम माली, नगर परिषद के कर्मचारी आंगनवाडी कार्यकर्ता व स्कूली छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

पूर्व विधायक सिसोदिया ने की मुख्यमंत्री से भेंट...

मंदसौर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न सड़कों के निर्माण का मांग पत्र सौंपा

मंदसौर, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। पूर्व विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया ने मंगलवार को भोपाल मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भेंट की। आपने मंदसौर विधानसभा क्षेत्र की 9 प्रमुख ग्रामीण सडकों को मंडी बोर्ड निधि या लोक निर्माण विभाग के माध्यम से स्वीकृत कर निर्माण किए जाने का निवेदन किया और इस संबंध में एक मांग पत्र भी सौंपा।

विधायक श्री सिसोदिया ने पत्र में कहा कि पूर्व में भोपाल मंत्रालय में आपसे भेंट करते हुए मंदसौर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न सडकों का निर्माण मंडी बोर्ड निधि या लोक निर्माण विभाग से स्वीकृत किए जाने का आग्रह किया था। मेरा पुन: आग्रह है कि यह सडकें अति महत्वपूर्ण है, अत: प्राथमिकता के आधार पर

फरवरी मार्च 2024 के आम बजट में इन सडकों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाए। श्री सिसोदिया ने पत्र में ग्राम भालोट से अचेरा 4 किलोमीटर, ग्राम माऊखेडी से बनी 3 किलोमीटर, ग्राम कोचवी से घटावदा 3 किलोमीटर, ग्राम देहरी से खजुरिया सारंग ढाई किलोमीटर, ग्राम करौली से कल्याणपुरा (राजस्थान) 2 किलोमीटर, ग्राम सरसोद से गुराडिया शाह 4 किलोमीटर, ग्राम डोराना से जवासिया फंटा 2 किलोमीटर, ग्राम निपानिया मेघराज से सेतखेडी रेलवे फाटक 2 किलोमीटर एवं ग्राम सिंदपन से ग्राम साबाखेड़ा 3 किलोमीटर के सडक निर्माण का आग्रह इस पत्र के माध्यम से किया है।

बच्चों को कुपोषण एनीमिया और बीमारियों से बचाव का प्रबंधन करने की दिशा में कार्य करें- डॉ.भारती

नीमच, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। 0 से 5 वर्ष आयु के बच्चों का सर्वेक्षण कर उन्हें कुपोषण एनीमिया, दस्त रोग, निमोनिया जन्मजात विकृतियों और अन्य जानलेवा बीमारियों से बचाने की दिशा में स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सी एच ओ कार्य करें। यह बात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संगीता भारती ने 24 जून से 27 अगस्त तक आयोजित होने वाले दस्तक अभियान के उन्मुखीकरण प्रशिक्षण के दौरान कहीं। सीएमएचओ ने मैदानी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया, कि दस्तक अभियान के दौरान आशा, आंगनवाडी कार्यकर्ता और एएनएम का संयुक्त दल बनाया जाए और कार्यों की मॉनिटरिंग सीएचओ द्वारा की जाए। कार्यशाला के दौरान जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ.बी.एल.सिसोदिया ने कहा, कि शिशु जन्म के तुरंत बाद स्तनपान, 6 महीने तक केवल स्तनपान, 6 महीने बाद पूरक पोषण आहार दिए जाने संबंधी व्यवहारों को अपनाने से शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। उज्जैन संभाग के न्यूट्रीशनल इंटरनेशनल के संभागीय समन्वयक श्री आशीष पुरोहित एवं एविडेंस एक्शन के कपिल यति ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बच्चों में होने वाला गंभीर कुपोषण पहचानने की पद्धतियां सिखाई।

ग्रीष्मकाल में लगाएं संस्कारों की पाठशाला...

मंदसौर, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। ग्रीष्मकालीन अवकाश विद्यार्थियों के साथ ही पूरे परिवार के लिए भी वर्ष का एक महत्वपूर्ण समय होता है। ग्रीष्मकाल अवकाश लगते ही बच्चे एवम माता पिता के चेहरो पर रौनक लोट आती है क्योंकि छुट्टियों के यह दिन वर्षभर प्रतीक्षा के बाद ही तो आते है। ऐसे में इस ग्रीष्मकालीन अवकाश की सभी को प्रतीक्षा रहती है। भारतीय परंपरा में ग्रीष्मकालीन अवकाश को कम से कम बच्चो और महिलाओ द्वारा ननिहाल, मायका में मनाने की परंपरा है। बच्चे छुट्टियां बिताने के लिए अपने रिश्तेदारो, संबंधियों या यूं कहे की नाना नानी, मोसी, भुआ के साथ ही अन्य रिश्तेदारो के यहा भी पंहुच जाते है। कुल मिलाकर पहले विद्यालय की छुट्टियां होते ही बच्चो का रुख रिश्तेदारो के घरो की और हो जाता था। ऐसे में माता पिता और दादा दादी के साथ ही नाना नानी को भी नाती पोती के रूप में एक नया वातावरण गर्मी में बतियाने, मनोरंजन करने, एक दूसरे को सीखने समझने के रूप में व्यतीत होता था लेकिन अब ग्रीष्मकालीन अवकाश के मायने, महत्व और उसको व्यतीत करने के तौर तरीके बहुत कुछ बदल गए है। इसलिए यह परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। इसकी अनुपस्तिथि विकृति एवम अन्य गलाकाट प्रतिस्पर्धाओं को भी तेजी से बढावा दे रही है। इसलिए ग्रीष्मकालीन अवकाश की वह संस्कारो के बीजारोपण वाली पद्धति पुन: लोटाने का प्रयास भी सतत होना आवश्यक है। ग्रीष्मकालीन अवकाश पर एकल परिवार की अवधारणा ने तेजी से प्रहार किया है। इसमें शहरी क्षेत्रो में तो और अधिक स्तिथि बिगडती दिखाई दे रही है क्योंकि हर कोई हम दो हमारे दो की विचारशेली को इस कदर अपना चुका है की कोई घंटे भर के लिए भी घर आ जाए तो बोझ लगने लगता है। परिवार में ही जब संयुक्त के स्थान पर एकल परिवार विचार का तेजी से प्रसार हो रहा है उस स्तिथि में बच्चो के बाल मस्तिष्क में यह विचार केसे बिजारोपित किया जाए की संगठित रहकर, संयुक्त परिवार में रहकर, सामूहिक रूप से रहकर ही प्रत्येक समस्या का समाधान संभव है। जब इस तरह का विचार प्रत्येक बालक बालिका में पल्लवित होगा तो समाज राष्ट्र की मजबूत नीव का निर्माण संभव होगा। इसके लिए भेदभाव, जातिवर्ग भेद को त्यागने की प्रवृति बडाने के लिए बच्चो को अपने कालोनी मोहल्ले में उंच्च नीच से परे सभी गरीब अमीर बच्चो को एक साथ गर्मी के अवकाश में खेलने रचनात्मक गतिविधियों को मिलकर बढावा देने की प्रवृति भी समाज संगठन की दृष्टि से संस्कारो की पाठशाला का काम करेगी। कुल मिलाकर इस अवकाश में माता पिता अपने बच्चो की रुचियों और कोशल को निखारने के साथ ही उन्हे धार्मिक, ऐतिहासिक, देश की भौगोलिक जानकारी, श्रेष्ठलेखको की कहानियाऔर महान महापुरुषो के जीवन चरित्र के अध्ययन के लिए प्रेरित करे। भारतीय इतिहास से अवगत कराने वाले, गौरव प्रदान करने वाले स्थलो, स्मारको का भी भ्रमण करवाएं ताकि बच्चो को अपने गोरवशाली इतिहास का भी ज्ञान हो सके। इससे उनके अंदर निश्चित रूप से परिवार व सामाजिक दायित्व का बोध होने के साथ ही देशभक्ति का भाव भी जाग्रत होगा।

गौरव सोनी, मंदसौर

तेलिया तालाब और चम्बल कॉलोनी में पौधारोपण

मंदसौर, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। भारतीय मजदूर संघ मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार 5 से 10 जून तक पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित करने तथा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देने के तहत भारतीय मजदूर संघ जिला मन्दसौर द्वारा स्थानीय तेलिया तालाब तथा चम्बल कालोनी परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अधीक्षण यंत्री राजेशचंद्र जैन एवं कार्यपालन यंत्री

प्रेम पालीवाल, सहायक यंत्री पंकज कुमावत थे। भारतीय मजदूर संघ के विशेष अतिथि विभाग प्रमुख गोपाल जामलिया थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा ने की। संचालन पर्यावरण जिला प्रभारी दिनेश पंवार ने किया। पौधारोपण कार्यक्रम पश्चात जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा के नेतृत्व व विभाग प्रमुख गोपाल जामलिया, वरिष्ठपेंशनर नागरिक महासंघ के जिला अध्यक्ष अशोक रामावत के मार्गदर्शन में, जिला कलेक्टर कार्यालय पर जाकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन पर्यावरण प्रभारी दिनेश पंवार ने किया। इस अवसर पर उम्मेन्द्र सिंह चौहान, नवीन गोड, दीपेन्द्र चौहान, मनोज पटेल, ललित पाल, नारायण शर्मा, आशा उषा कार्यकर्त्ता महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष भारती सोलंकी, जिला अध्यक्ष संतोष सालवी, कोषाध्यक्ष निधि पारिख, राज्य कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष प्रदीप झा, धाकड बिजली कर्मचारी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश पाण्डेय, दशरथ शर्मा बिजली कामगार सोसायटी प्रबंधक पारसमल जैन सहायक मनोज बसेर, गजुवेन्द्रसिंह भदौरिया सेवानिवृत्त एवं पेंशनर नागरिक महासंघ जिला सचिव चन्द्रकान्त शर्मा, आदि उपस्थित थे। आभार भारतीय मजदूर संघ जिला मंदसौर के प्रभारी मंत्री संदीपसिंह शक्तावत ने माना। यह जानकारी बिजली कर्मचारी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश पाण्डेय ने दी।

शौचालय में अचेत मिला युवक, नही हुई पहचान

पिपलियामंडी, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। कृषि उपज मंडी के पीछे, सहकारी दाल मिल के पास स्थित सार्वजनिक शौचालय में मंगलवार सुबह एक युवक अचेत अवस्था में मिला। जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भर्ती कराया, युवक की पहचान नही हो पाई। जानकारी के अनुसार मंगलवार प्रात: 8 बजे करीब शौचालय के अन्दर एक युवक अचेत अवस्था में पडा होने की सूचना पर पुलिस मौके पहुंची, युवक को बाहर निकलवाया, जो बोलने की स्थिति में नही था। उसके पैर जख्मी हो रहे थे, खून निकल रहा था। टीआई नीरज सारवान का कहना है कि युवक नशे में था। पैर में बीमारी होने से वे जख्मी हो रहे थे, उसे अस्पताल भर्ती कराया है, पहचान नही हो पाई है।

मंदिर पर जल चढ़ाने गया युवक लापता

पिपलियामंडी, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। गांव बेलारा से एक युवक लापता हो गया। पिता ने गुमशुदगी दर्ज कराई। बेलारा निवासी लालू पिता मांगू भारती गोस्वामी ने पिपलिया थाने पर शिकायत दर्ज कराई कि उसका 19 वर्षीय पुत्र संतोष भारती सुबह 6.30 बजे गांव में शिव मंदिर पर जल चढाने के लिए गया था। उसके बाद घर पर नही आया। उसका मोबाइल भी घर पर रखकर गया।

श्री सांवलिया गौशाला में बैल की मृत्यु होने पर दी गई समाधी

मंदसौर, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। ग्राम कुंचडौद में श्री सांवलिया गौशाला

कुंचडौद में निवासरत लगभग 500 गौवंश है इनमें से भगवान भोलेनाथ के प्रिय वाहन एक नंदी (बैल) की मृत्यु होने पर गौशाला के गौसेवकों द्वारा योग गुरू बंशीलाल टांक के सानिध्य और मार्गदर्शन में नंदी को जमीन में जेसीबी मशीन से गौशाला परिसर में गहरा गड्ढा खोदकर समाधी दी गई। समाधी से पूर्व नंदी के सिंगों को रंगा गया। सम्पूर्ण शरीर को कफन (श्वेत वस्त्र) ओढाकर, पुष्पमाला, गुलाल से पूजा अभिषेक कर समाधी दी गई।

योग गुरू बंशीलाल टांक ने बताया कि हिन्दू धर्मशास्त्रों-सनातन हिन्दू धर्म में नन्दी जिसे वृषभ भी कहा जाता है इसे साधारण पशु-बैल नहीं मानकर उसे साक्षात भगवान शंकर के गणों में मानकर नन्दी को भगवान भोलेनाथ का वाहन होने का गौरव भी प्राप्त है। गौशाला में निवासरत नन्दी को मृत्यु से पूर्व बीमार होने पर गौशाला चिकित्सक प्रवीण शर्मा, डॉ. पंचोली तथा पशु चिकित्सालय के चिकित्सकों द्वारा यथेष्टचिकित्सा की जाती रही। गौशाला में लगभग 2 माह से 500 गौवंश तथा विगत दिनों 46 ट्रकों से जप्त 590 गौवंश (बैलों) में से गौशाला में रखे गये 50 गौवंश (बैलों) की भी हरी घास-चरी, बांटा (सुदाना), भूसा आदि भरपूर आहार के साथ ही पानी आदि की पर्याप्त व्यवस्था होकर अच्छी सेवा की जा रही है।

प्रदेश के सभी जिलों का आगामी पांच साल के विकास का रोडमेप बनाए-डॉ.यादव

मुख्यमंत्री ने की जल गंगा संवर्धन अभियान की प्रगति समीक्षा

नीमच, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। प्रदेश के सभी जिले अपने-अपने जिले और विधानसभा क्षेत्रों का आगामी पांच सालों में विकास का रोडमेप बनाएं। जिले और प्रदेश को आगे बढाने एवं विकास के लिए प्राप्त4 सुझावों को भी रोडमेप में शामिल करें। जनसहभागिता से प्रदेश को विकास की राह पर और आगे बढाने का प्रयास करें। यह बात प्रदेश के मुख्यममंत्री डॉ.मोहन यादव ने मंगलवार को निवास स्थित समत्व भवन में वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्य म से प्रदेश में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सभी जिलों में जल संरक्षण एवं जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के कार्यो की समीक्षा करते हुए कही। इस मौके पर मंत्री श्री कैलाश विजय वर्गीय एवं मुख्या सचिव एवं अन्यष वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौजूद थे।

इस वीसी में बताया गया कि प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 3672 करोड के काम हो रहे है। यह अभियान गंगा दशहरा तक चलेगा। इसके माध्य म से जल संरचनाएं पुराने कुएं,

बावडी, तालाब, नदी, पोखर, आदि सभी जल संरचना को पुर्नजीवित करने का काम किया जा रहा है। वीडीयों कांफ्रेंसिंग में मुख्यामंत्री डॉ.यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिलों में अब तक हुए कार्यो और भविष्या में प्रस्ता वित कार्यो की जानकारी भी ली। नीमच के एनआईसी कक्ष में इस वीसी में विधायक जावद श्री ओमप्रकाश सखलेचा, नीमच विधायक श्री दिलीप सिह परिहार, मनासा विधायक श्री अनिरूद्ध मारू, कलेक्टीर श्री दिनेश जैन, एसपी श्री अंकित जायसवाल, जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद, एवं डीएफओ श्री एस.के.अटोदे भी मौजूद थे।

विधायक श्री सखलेचा व श्री मारू ने वन राजस्वस, सीमा विवादों के निराकरण का सुझाव दिया:- इसी वीडियों कांफ्रेंसिंग में विधायक जावद श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने वन राजस्व सीमा भूमि विवाद के प्रकरणों के निराकरण का सुझाव देते हुए कहा, कि नीमच जिले में लगभग पांच हजार प्रकरण वन राजस्वन सीमा विवाद के है। उन्होरने इन प्रकरणों के निराकरण के लिए जिले में पृथक से सेवानिवृत्ते प्रशासनिक अधिकारी, (डिप्टीश कलेक्टकर) की पदस्थाणपना करने का सुझाव भी दिया। विधायक श्री अनिरूद्ध मारू ने भी वन, राजस्वन सीमा विवाद का उल्ले ख करते हुए कहा कि एक बार संयुक्तर निरीक्षण कर राजस्व वन भूमि विवाद का स्था ई हल हो जाना चाहिए और जो सीमा निर्धारित हो, उसी पर ही वन व राजस्वा विभाग कायम रहे। ऐसी व्यिवस्था सुनिश्चित हो, जिससे कि किसानों को कोई असुविधा ना हो। विधायक जावद व मनासा के सुझाव पर मुख्य्र सचिव म.प्र.ने ए.सी.एस.डॉ.राजेश राजोरा को वन राजस्वत सीमा विवाद के प्रकरणों का समुचित समाधान करवाने के लिए कहा है।

मंदसौर मंडी भाव

उपज	आवक बोरी में	न्यूनतम	अधिकतम
मक्का	38	2310	2455
उडद	9	2391	6262
सोयाबीन	4000	3950	4640
गैहु	6050	2452	3001
चना	379	6000	6611
मसुर	200	5510	6281
धनिया	268	5001	7400
लहसुन	11500	5500	20000
मैथी	1065	4000	6219
अलसी	1251	5500	6100
सरसो	376	4799	5450
तारामीरा	0000	0000	0000
इसबगोल	101	10500	14200
प्याज	4500	800	2221
कलोंजी	25	12501	19001
डॉलर	18	6452	9001
तिल्ली	375	9600	12100
मटरसुखी	14	2200	4999
असालीया	143	9100	10053

कालाखेत स्थित बावड़ी में राज्यसभा सांसद, नपा अध्यक्ष, कलेक्टर, सीईओ ने किया श्रमदान

कलेक्टर ने बावड़ी तक के पहुंच मार्ग के अवरोध को दूर करने के दिए निर्देश

मंदसौर, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राज्यसभा सांसद श्री बंशीलाल गुर्जर, कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव, सीईओ जिला पंचायत श्री कुमार सत्यम, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर ने कालाखेत स्थित बावडी पर श्रम दान किया। इस दौरान कलेक्टर श्री यादव ने बावड़ी तक पहुंचने वाले पहुंच मार्ग के अवरोध को दूर करने के लिए नगर पालिका एवं तहसीलदार को निर्देश दिए। बावड़ी की साफ-सफाई करने में सामाजिक कार्यकर्ताओं, समाजसेवियो ने भी भरपूर योगदान दिया। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत पूरे जिले में साफ सफाई के साथ महिलाओं द्वारा कलश यात्रा भी निकाली जा रही है। ग्रामीणों जनों के साथ हर गांव का दल तालाब, नाले की सफाई में जुट गया है। सैकड़ो महिला, पुरूष तथा युवा, समाजसेवी श्रमदान कर रहे हैं। श्रम दान के दौरान महिलाओं, पुरुषों में विशेष उत्साह दिख रहा था, श्रमदान के दौरान सभी जल संरक्षण के गीत भी गा रही है। श्रमदान के बाद सभी में खुशी की लहर दिखने लगी, सभी ने लगातार सफाई का संकल्प लिया। सांसद, कलेक्टर ने जल की महत्वा से सभी को अवगत कराया तथा गांव के कुएं, तालाब की सफाई की समझाइश दी। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत भूमि जल व वर्षा जल को सहेजने के लिए पुरानी जल संरचनाओं को पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। मंदसौर शहर सहित जिले के अन्य कस्बों एवं ग्रामीण अंचल में जन सहभागिता से जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हुआ है। यह अभियान 16 जून तक चलेगा। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थानीय लोगों ने भी हाथ बटाया। भूमि का जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। हमें वर्षा जल सहेजने के लिए साझा प्रयास करने होंगे। यह काम अकेले शासन व प्रशासन से संभव नहीं है। इसमें समाज को भी कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करना होगा। जिले में हर दिन जल संरचनाओं को सहेजने का कार्य किया जा रहा है। जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों से होकर बह रहीं नदियों, सहायक नदियों, बाँध, तालाब व अन्य जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण कार्य के लिये सुनियोजित योजना बनाकर काम किया जा रहा है।

गड़बड़ी कहीं भी हो, सरकार कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी- मुख्यमंत्री

भोपाल, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। प्रदेश में गडबडी किसी भी तरह की स्वीकार नहीं की जाएगी। जहां कहीं नियमों के विपरीत काम होगा, वहां कडी कार्रवाई होगी। अवैध खनन हो या फिर कानूनी व्यवस्था से जुडे हुए मामले त्वरित कार्रवाई की जाएगी। रोजगार सरकार की प्राथमिकता में है और इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने योजनाएं बंद करने को लेकर काफी दुष्प्रचार किया लेकिन हमने कोई भी योजना बंद नहीं की बल्कि सभी वर्गों को लाभान्वित करने का काम किया है।

एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत 13 जुलाई से प्रदेश में होगी। 16 जुलाई से हेलीकॉप्टर से धार्मिक पर्यटन सेवा को प्रारंभ किया जाएगा। यह बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने 6 माह के कार्यकाल का ब्यौरा देते हुए मंत्रालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि सरकार के गठन को छह माह हो चुके हैं। तीन माह लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में बीते। शांतिपूर्ण चुनाव करना चुनौती थी। विपक्षी दल सहित सबने मिलकर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए हैं। लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसके अनुरूप ही प्रदेश से छह मंत्री बनाए गए हैं। छह माह की अवधि में सरकार ने कई काम किए हैं। केन- बेतवा लिंक परियोजना के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं। वन भूमि से जुड़ा हुआ जो विषय था, उसका भी समाधान कर लिया गया है। चंबल-पार्वती-काली सिंध परियोजना को लेकर 20 वर्ष से जो विषय उलझा हुआ था, उसका भी समाधान कर लिया गया है। गांधी सागर जलाशय के जल उपयोग को लेकर जो विवाद था उसके समाधान की दिशा में भी आगे बढ़ गए हैं।

प्रदेश में निवेश भी बढ़ रहा है- 60 हजार करोड रुपये के निवेश से सीहोर जिले के आष्टा में बड़ा प्लांट लगने जा रहा हैं। इससे 20 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। उज्जैन में क्षेत्रीय इन्वेस्टर समिट की गई थी, जिसमें एक लाख करोड रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। निश्चित तौर पर इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जबलपुर, ग्वालियर, रीवा सहित स्थान पर भी ऐसे ही समिट की जाएंगी। किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता में है। इस वर्ष अभी तक 48 लाख मीट्रिक टन गेहूं छह लाख किसानों से खरीदा जा चुका है। हमारा प्रयास यही है कि किसानों को उपज का उचित मूल्य मिले।

125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जा रहा- हमने पहले ही कहा था कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी। लाडली बहनाओं से किया हुआ वचन निभाया है। एक करोड 29 लाख बहनों को अब तक 9,455 करोड रुपये दिए जा चुके हैं। लाडली लक्ष्मी योजना में बीते छह माह में 73,880 बालिकाओं को 24 करोड़ रुपये दिए गए हैं। 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के वादे को निभाते हुए अब तक 45 लाख 90 हजार बहनों के खातों में 118 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। 11 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के साथ सात लाख हितग्राहियों को रोजगार योजनाओं के अंतर्गत पांच हजार करोड रुपये के ऋण स्वीकृत कराए हैं। सुशासन सरकार की प्राथमिकता में है। पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए अभियान चल रहा है। जल संरचनाओं के पुनर्जीवन के लिए गतिविधियां संचालित हो रही हैं।

कहीं भी पौधों को काटा नहीं जाएगा- ऐसी कोई भी योजना सरकार नहीं बनाएगी जिससे पर्यावरण को नुकसान हो। जहां आवश्यकता होगी वहां अन्य विकल्पों को प्राथमिकता दी जाएगी। अनियंत्रित ध्वनि विस्तार की यंत्रों को हटाने की कार्रवाई की गई है। सरकार का प्रयास है कि कालेज, मंत्री और अधिकारी गांव को गोद लें ताकि वहां पर समुचित विकास के काम हो सके। रोजगार के लिए गंभीरता के साथ प्रयास किया जा रहे हैं। भोपाल, उज्जैन, जबलपुर आदि जिलों में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विस्तार की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। मैं स्वयं बेंगलुरु और हैदराबाद जाऊंगा और वहां बडी कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर उन्हें मध्य प्रदेश में आने के लिए प्रेरित करूंगा।

जिले में सार्वजनिक जल स्त्रोतों से अतिक्रमण हटवाए-जैन

नीमच, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। जिले के सभी नगरीय निकाय, स्थानीय निकाय पंचायतें एवं राजस्व अधिकारी सार्वजनिक जल स्त्रोतों, तालाबों, कुओं, बावडियों, नदी, नालों से अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर हटवाए। जल गंगा संर्वधन अभियान के तहत जल स्त्रोतों की साफ-सफाई, गहरीकरण के कार्य प्राथमिकता से करवाएं और इन कार्यो में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी प्राप्त करें। यह निर्देश कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जल गंगा संवर्धन अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को दिए।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद, एडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कुओं, बावडियों व नालों की साफ-सफाई का कार्य निरंतर होना चाहिए। प्रत्ये क ग्राम पंचायतों में तालाबों व अन्य जल संरचनाओं से मिट्टी निकालने का कार्य करवाया जावे। हर ग्राम पंचायत में अंकुर उपवन के तहत 200 पौधे रौपे जाएंगे। कलेक्टर ने जल गंगा संवर्धन अभियान से संबंधित दीवार लेखन का कार्य करवाने के निर्देश सभी जनपद सीईओं और सीएमओ को दिए। जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद ने जल गंगा संवर्धन अभियान की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुनत की व अब तक की प्रगति से अवगत कराया। बैठक में कलेक्टर श्री जैन व्दांरा 18 से 20 जून तक जिले में आयोजित होने वाले स्कूल चले हम अभियान के तहत प्रवेशोत्सतव कार्यक्रम की तैयारियों की भी विस्ताकर से समीक्षा की। उन्होतने 21 जून को अंतर्राष्ट्री य योग दिवस कार्यक्रम की तैयारियों की भी जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

जल प्रदाय योजना अंतर्गत ग्रामों में सिखाया जल गुणवत्ता परीक्षण

मंदसौर, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत गांधीसागर 1 समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिसके अंतर्गत ग्रामीणों को जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु एफटीके के माध्यम से जल की गुणवत्ता परीक्षण करना सिखाया गया। पर्यावरण बचाने हेतु सभी लोगों से ज्यादा से ज्यादा जल स्त्रोतों को संरक्षित एवं संवर्धन करने का कार्य करना चाहिए जिससे हम हमारी भावी पीढ़ी को जीवन जीने की कार्यशैली सिखा सकें और हमारे पशु-पक्षी भी सुरक्षित रह सकें। हम सभी को वृक्ष लगाने का कार्य करना चाहिए किंतु पौधा रोपण वही करें जहां पानी हो, इससे हमारा पानी भी बचेगा और हमारे वृक्ष भी बड़े होंगे इसलिए पौधा रोपण स्थान और जगह देखकर ही करें। प्रकृति की रक्षा, पर्यावरण के संरक्षण हेतु सभी को शपथ दिलवाई गई।

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में हो रहे हैं बूंद-बूंद सहेजने के प्रयास

मंदसौर, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में कहीं नदी-नाला तो कहीं तालाब और कहीं पर्कुलेशन टैंक तो कहीं कंटूर ट्रैंच बनाने में ग्रामीणजन जुटे हैं। जिले की जल संरचनाओं, तालाब, बावड़ी का गहरीकरण सरकारी योजनाओं एवं जन सहयोग से हो रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत वर्षा जल की बूँद-बूँद सहेजने के लिये सरकार व समाज के साझा प्रयासों से जल संरक्षण के यह सब काम हो रहे हैं। तालाब के पानी का उपयोग ग्रामीणों की निस्तार संबंधी जरूरतों के साथ-साथ सिंचाई में भी होगा।

राज्य सरकार की पहल पर शुरू हुए जलगंगा संवर्धन अभियान केतहत भूमि जल व वर्षा जल को सहेजने के लिए पुरानी जल संरचनाओं को पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। मंदसौर शहर सहित जिले के अन्य कस्बों एवं ग्रामीण अंचल में जन सहभागिता से जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हुआ है। यह अभियान 16 जून तक चलेगा। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थानीय लोगों ने भी हाथ बटाया। भूमि का जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। हमें वर्षा जल सहेजने के लिए साझा प्रयास करने होंगे। यह काम अकेले शासन व प्रशासन से संभव नहीं है। इसमें समाज को भी कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करना होगा। जिले में हर दिन जल संरचनाओं को सहेजने का कार्य किया जा रहा है। जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों से होकर बह रहीं नदियों, सहायक नदियों, बाँध, तालाब व अन्य जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण कार्य के लिये सुनियोजित योजना बनाकर काम किया जा रहा है।

पशुपतिनाथ मंदिर से लेकर तीन छतरी बालाजी तक के सभी मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया जाए-सांसद

मंदसौर, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। पशुपतिनाथ लोक व मंदिर के सौंदर्यीकरण को लेकर एक बैठक आज जिला प्रशासन के साथ पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में रखी गई जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ में शहर के गणमान्य नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं उपस्थित थे। बैठक में पशुपतिनाथ मंदिर के विकास व उसके सौंदर्यीकरण को लेकर विस्तार से चर्चा हुई जिस पर सांसद गुप्ता ने अपने अनेक सुझाव रखें जिसमें प्रमुखता के साथ उन्होंने कहा कि पशुपतिनाथ मंदिर से तीन छतरी बालाजी तक नदी के किनारे एक पैदल रास्ता बनाया जाए क्योंकि इस मार्ग पर अति प्राचीन मंदिर उपस्थित हैं जिस धर्म प्रेमी जनता इन मंदिरों के दर्शन का लाभ भी ले सके। साथ ही पशुपतिनाथ लोक से इन मंदिरों के सौंदर्यीकरण को भी जोड़ा जाए उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि पशुपतिनाथ लोक के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए साथ ही आने वाले तीर्थ यात्रियों को मंदिर परिसर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो इसका भी विशेष प्रबंध किया जाए। उन्होंने आने वाले 16 तारीख को गंगा दशहरे पर होने वाले आयोजित कार्यक्रमों की रूपरेखा के लिए भी प्रशासन को निर्देशित किया। सांसद गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पशुपतिनाथ मंदिर विश्व की ऐतिहासिक धरोहर है और शहर की सद्भावना का प्रमुख केंद्र है अत: इसके निर्माण में सभी भावनाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में राज्यसभा सांसद श्री बंशीलाल गुर्जर, विधायक विपिन जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष बसंत शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रामादेवी गुर्जर, रेड क्रॉस चेयरमैन प्रीतेश चावला, प्रेस क्लब अध्यक्ष बृजेश जोशी, दिलीप शर्मा, द्रष्टानंद नेनवानी मनीष भावसार गौरव अग्रवाल राजेश नामदेव ज्योति प्रकाश जाजपुरिया चेतन जोशी कन्हैयालाल सोनगरा राजाराम तंवर मनोहर नेनवानी सहित शहर के विभिन्न गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

देशी कट्टे के साथ एक धराया

भानपुरा, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। थाना पुलिस ने हथियारों की तस्करी कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 12 बोर का देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। आरोपी पर अवैध हथियार रखने के आरोप में प्रकरण दर्ज किया है।

भानपुरा थाना पुलिस के अनुसार मुखबीर से सूचना मिली थी कि लेदी चौराहा पर गोविंद लोहार अवैध हथियार के साथ बैठा है। दबिश देकर गोविंदलाल पिता लक्ष्मणलाल लोहार उम्र 26 साल निवासी सरकन्या भेसोदा मंडी थाना भानपुरा को हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली गई। उसके कब्जे से 12 बोर का देशी कट्टा और कारतूस बरामद किया है। मामले में पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

जनसुनवाई में 58 ग्रामीणों की समस्याएं सुनी

मंदसौर, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने सुशासन भवन सभाकक्ष में ग्रामीण जनों की समस्याएं सुनी प्रति मंगलवार की तरह जिला कलेक्ट्रेट (सुशासन भवन) में साप्ताहिक जनुसनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसुनवाई में जिले भर से आए 58 आवेदकों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर श्री यादव ने अधिकारियों को समय सीमा में निराकरण करने के अधिकारियों को निर्देश दिये। जनसुनवाई में आवेदकों ने अपनी समस्या/ शिकायत/ मांग/ आर्थिक सहायता संबंधी आवेदन दिये। जनसुनवाई में दौरान वरिष्ठप्रशासनिक अधिकारियों ने सभी आवेदकों से आवेदन पत्र प्राप्त कर उन पर समुचित कार्यवाही के लिये विभाग प्रमुखों की ओर प्रेषित किया। जनसुनवाई में बीपीएल सूची में नाम जुडवाने, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास मंजूर करने, निजी भूमि पर अवैध अतिक्रमण, भूमि विवाद, बीमारी सहायता, आपसी विवाद, शिक्षा ऋण दिलाने, सामुदायिक सुविधा घर (कम्युनिटी टायलेट) बनवाने आदि विषयों के आवेदन प्राप्त हुये। जिनके निवारण हेतु संबंधित विभागाधिकारियों को निर्देश दिये। जनसुनवाई के दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री कुमार सत्यम, जिला अधिकारी उपस्थित थे।

विवादित स्टेण्ड पर किसी ने...

पेज 1 से जारी

पुलिस व प्रशासन ने कोई कार्रवाई नही की। प्रशासन नींद निकाल रहा है, उसे बड़ी घटना का इंतजार है। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष मंगलेश सूर्यवंशी ने बताया कि आरक्षित जगह पर रात्रि में चुपके से हनुमान प्रतिमा लगा दी गई, प्रशासन संज्ञान ले, प्रतिमा के लिए आरक्षित जगह को खाली करवाकर भगवान की प्रतिमा को कई ओर जगह स्थापित की जाए। अगर एसा नही किया जाता है तो बाबा साहब के सम्मान में आन्दोलन के लिए सभी कार्यकर्ता तैयार रहे।

पुलिस, प्रशासन ने झाड़ा पल्ला:- पिपलिया टीआई नीरज सारवान का कहना है पुलिस इसमें कुछ नही कर सकती है, नगर परिषद् क्षेत्र का मामला है, सीएमओ कार्रवाई करेंगे, उनसे जानकारी लो। सीएमओ प्रवीण सेन से चर्चा की तो उनका कहना था हमने वर्तमान में किसी की भी प्रतिमा के लगाने की स्वीकृति नही दी है, वरिष्ठअधिकारियों को अवगत कराकर मार्गदर्शन लिया जाएगा। एसडीओपी नरेन्द्र सोलंकी का कहना है कोई शिकायत नही आई है, नगर परिषद् क्षेत्र का मामला है। नगर परिषद् से इस संबंध में जानकारी मंगवाई है। एसडीएम राहुल चोहान से मोबाइल नम्बर 9109479137 पर लगातार संपर्क किया, लेकिन उनका मोबाइल स्वीच ऑफ मिला।

किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी सस्ती बिजली

भोपाल, 11 जून गुरु एक्सप्रेस। प्रदेश में किसान और घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार वर्ष 2024-25 में 24,420 करोड़ रुपये का अनुदान देगी। यह राशि विद्युत वितरण कंपनियों को दी जाएगी। इस बार विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में वृद्धि नहीं की है। वहीं, स्वास्थ्य संस्थाओं में वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए नियमित, संविदा और आउटसोर्स के 46,491 पद सृजित करके तीन वर्ष में भर्ती की जाएगी।

इन दोनों प्रस्तावों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृति दी गई। बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए छह हजार, सामान्य वर्ग के किसानों के लिए 13 हजार और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के किसानों के लिए पांच हजार करोड़ रुपये का अनुदान विद्युत वितरण कंपनियों को दिया जाएगा।

कई रिक्त पदों पर होगी भर्ती- वहीं बड़ा निर्णय करते हुए स्वास्थ्य संस्थानों में स्वीकृत एवं भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए 46,491 नए नियमित, संविदा और आउटसोर्स के पद सृजन की स्वीकृति दी गई। इनमें से 18,653 पदों की पूर्ति आगामी तीन वर्ष में की जाएगी। इस पर वार्षिक 343 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा।

बाकी 27,828 पदों की पूर्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से की जाएगी। इसी तरह निश्चेतना, मेडिकल, स्त्री रोग, शिशु रोग, रेडियोलाजिस्ट, अस्थि रोग और सर्जरी विशेषज्ञ के रिक्त के कुल स्वीकृत 12,14 पदों में से 50 प्रतिशत यानी 607 पदोन्नति के पदों भी सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा।

इस कारण नहीं हो रही थी भर्तियां- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पदोन्नति नियम न होने और सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण विशेषज्ञों की भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति पर लिए जा सकेंगे। अभी तक यह व्यवस्था नहीं थी।

3 विश्वविद्यालयों को सरकार देगी अनुदान- अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर, क्रांति सूर्यकांत टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन तथा क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना को अनुदान देने के संबंध में भी कैबिनेट ने निर्णय लिया। प्रत्येक नए विश्वविद्यालय की प्रारंभिक आवश्यकता के लिए तीन करोड रुपये के साथ ही प्रतिवर्ष ब्लाक ग्रांट भी दी जाएगी। पहले वित्तीय वर्ष के लिए 10 करोड रुपये का प्रविधान किया जाएगा। नवीन विश्वविद्यालयों के लिए 235 पद, भवन निर्माण के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय को 150 करोड़ रुपये और पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल के लिए 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी गई।

2024-25 को गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा- कैबिनेट ने गोवंश की रक्षा के लिए वर्ष 2024-25 को गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत प्रदेश में संचालित गौशालाओं को श्रेष्ठ संचालन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा, साथ ही सड़कों पर घायल गाय को उपचार के लिए ले जाने हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग व्हीकल को टोल नाकों पर व्यवस्था की जाएगी। गोशालाओं को समाज से जोड़ने के लिए जिलों में विभिन्न सामाजिक, मांगलिक व धार्मिक कार्यक्रम गोशालाओं में करने के लिए प्रेरित करने के साथ नई पीढ़ी को गोवंश के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए भी कार्यक्रम किए जाएंगे।

नरेंद्र मोदी को कैबिनेट ने दी बधाई- मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट के सभी सदस्यों ने नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी गई। साथ ही सभी सदस्यों ने प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर आए परिणाम, पार्टी का वोट शेयर 61 प्रतिशत पहुंचने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी।

❋ अंतिम यात्रा ❋

अत्यन्त दु:ख के साथ सुचित किया जाता है कि

मुकेश शर्मा, दिनेश शर्मा के पिताजी एवं कृष्ण कुमार, मोन कुमार, प्रसन्न कुमार, रसेन्द्र कुमार, अनिल कुमार, यशोधर्मन, नितेश के काकाजी और अश्विन, अंकित, अजय के दादाजी श्री राम कुमार जी पोस्ट ऑफिस वाले का स्वर्गवास दिनांक 11/06/24 को हो गया है। जिनकी अंतिम यात्रा 12/6/24 सुबह 10:00 बजे बापू नगर संजीत नाका मंदसौर से निकाली जावेगी।

❋❋❋ शोकाकुल ❋❋❋
शर्मा परिवार

स्वत्वाधिकारी, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक आशुतोष नवाल के लिए गुरु मीड्यिा एण्ड इंटरटेनमेन्ट कम्पनी, शक्ति नगर मन्दसौर से मुद्रित एवं 77 लक्ष्मीनगर, वेदान्त विहार मन्दसौर से प्रकाशित। (हर प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र मन्दसौर रहेगा) संपादक- आशुतोष नवाल RNI-MPHIN2006/20356
समाचार पत्र में छपे विज्ञापनों के लिए समाचार पत्र उत्तरादायी नहीं है एवं विज्ञापनो में प्रकाशित विचार विज्ञापनदाता की निजी राय है। इससे समाचार पत्र का कोई संबंध नहीं है। फोन 495831, मो. 9425105927,28 ashugurumds@gmail.com, ashu_guru2@yahoo.co.in